



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)



सं. 561]
No. 561]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 5, 2001/कार्तिक 14, 1923
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 5, 2001/KARTIKA 14, 1923

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2001

सा. का. नि. 825(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों—

(क) “अधिनियम” से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) अभिप्रेत है;

(ख) “परिशिष्ट” से इन नियमों का परिशिष्ट अभिप्रेत है;

(ग) “बंद गिरफ्तारी” से किसी भर्ती किए गए बल-सदस्य का उस बल या उस बल की किसी टुकड़ी या किसी क्वार्टर गार्ड चौकी, भवन या किसी गार्ड के प्रभार के अधीन शिविर के भीतर परिरोध अभिप्रेत है;

(घ) “मजिस्ट्रेट” से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 3 में यथानिर्दिष्ट कोई मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;

(ङ) “खुली गिरफ्तारी” से किसी भर्ती किए गए बल-सदस्य का, बल की किसी टुकड़ी द्वारा तत्समय दखल की हुई किसी बैरक, लाइन या शिविर की प्रसीमा के भीतर परिरोध अभिप्रेत है;

(च) “अनुसूची” अनुसूची से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(छ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ज) “हमला” आपराधिक बल “विश्वास करने का कारण” “सदोष अवरोध लगा देना” और “स्वेच्छया उपहति कारित करता है” पद के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके भारतीय दंड संहिता में हैं;

(झ) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके अधिनियम में हैं।

अध्याय 2

बल की संरचना

3. बल का गठन—(1) बल निम्नलिखित तीन शाखाओं से मिलकर बनेगा, अर्थात्—

- (i) कार्यपालक शाखा;
- (ii) अग्नि शमन सेवा शाखा; अर्थात्
- (iii) अनुसचिवीय शाखा।

(2) प्रत्येक शाखा ऐसे पर्यवेक्षक अधिकारियों (महानिदेशक से भिन्न) और भर्ती किए गए बल के सदस्यों से मिलकर बनेगी जो समय-समय पर महानिदेशक विनिर्दिष्ट करे।

4. बल की संरचना—पर्यवेक्षक अधिकारियों और बल के भर्ती किए गए सदस्यों को निम्नलिखित प्रवर्गों में रैंकों के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात् :—

(1) (क) पर्यवेक्षक अधिकारी

- (i) महानिदेशक;
- (ii) महानिरीक्षक;
- (iii) उप महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक (अग्नि शमन) और निदेशक, राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी;
- (iv) कमांडेंट, सहायक महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक (अग्नि शमन), कमांडेंट (अग्नि शमन), ग्रुप कमांडेंट, प्राचार्य, रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र, प्राचार्य, अग्नि शमन सेवा प्रशिक्षण संस्थान, सहायक निदेशक, राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी;
- (v) उप कमांडेंट और उप कमांडेंट (अग्नि शमन) और संयुक्त सहायक निदेशक राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी;
- (vi) सहायक कमांडेंट, उप प्राचार्य, रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र, सहायक कमांडेंट (कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) और सहायक कमांडेंट (अग्नि शमन) तथा उप सहायक निदेशक, राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी।

(ख) भर्ती किए गए सदस्य—

- (vii) निरीक्षक (कार्यपालक, आशुलिपिक, अनुसचिवीय, अग्नि शमन और आयुधिक);
- (viii) उपनिरीक्षक (कार्यपालक, आशुलिपिक, अनुसचिवीय, अग्नि शमन और आयुधिक);
- (ix) सहायक उप निरीक्षक (कार्यपालक, अनुसचिवीय, अग्नि शमन और आयुधिक);
- (x) हैड कांस्टेबल, (ड्राईवर, कार्यपालक, अग्नि शमन और आयुधिक);
- (xi) कांस्टेबल (कार्यपालक, अग्नि शमन, आयुधिक); और
- (xii) अनुचर (रसोइया, कहार, झाड़ूकस, मोची, नाई, बढई, दर्जी, धोबी, चार्ज मैकेनिक, मोटर पंप परिचारक, स्विच बोर्ड परिचारक और पेंटर)।

मद सं. (xii) में उल्लिखित रैंकों से भिन्न रैंकों के उपरोक्त प्रवर्गों के प्रत्येक प्रवर्ग उस प्रवर्ग से नीचे उल्लिखित रैंक से अव्यवहित वरिष्ठ होंगे।

(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में कमांडेंट, उप कमांडेंट, सहायक कमांडेंट, निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, हैड कांस्टेबल, कांस्टेबल और अनुचरों के प्रति निर्देश को उपनियम (1) के मद (iv) से मद (xii) में विनिर्दिष्ट यथास्थिति पर्यवेक्षक अधिकारियों या भर्ती किए गए बल-सदस्यों की सभी या किसी रैंक के प्रति निर्देश क्रमशः सम्मिलित समझा जाएगा।

5. स्थानीय रैंक का प्रदान किया जाना—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, महानिदेशक बल के बेहतर कार्यकरण के लिए जब कभी भी उसके द्वारा आवश्यक समझा जाए बल के किसी अधिकारी को उसके द्वारा धारित रैंक से निम्नलिखित उच्चतर रैंक केन्द्रीय सरकार द्वारा पुष्टि किए जाने के अधीन रहते हुए स्थानीय रैंक के रूप में प्रदान कर सकेगा :—

- (i) महानिदेशक द्वारा केवल कमांडेंट तक जिसमें यह रैंक भी सम्मिलित है स्थानीय रैंक प्रदत्त की जाएगी।
- (ii) उप महानिरीक्षक और उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों को स्थानीय रैंक गृह मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् प्रदत्त की जाएगी।

(iii) स्थानीय रैंक प्रदत्त करने की शक्ति महा निदेशक द्वारा उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी को आगे प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी।

(iv) बल का वह अधिकारी जिसे स्थानीय रैंक प्रदान की गई है—

(क) कमान का प्रयोग करेगा और उस रैंक को धारित करने वाले अधिकारी की शक्तियां उसमें निहित होंगी;

(ख) उस रैंक को धारित करने से प्रविरत हो जाएगा जब ऐसी रैंक प्रदान किए जाने की केन्द्रीय सरकार द्वारा 21 दिन के भीतर पुष्टि नहीं की जाती है, या महा निदेशक द्वारा जब ऐसा आदेश दिया जाता है या जब वह उस नियुक्ति को धारित करने से प्रविरत हो जाता है जिसके लिए वह रैंक प्रदान की गई है।

(ग) ऐसी रैंक धारित करने के लिए कोई अतिरिक्त वेतन और भत्ते के लिए हकदार नहीं होगा।

(घ) ऐसी रैंक धारित करने के आधार पर बल के अन्य अधिकारी पर किसी ज्येष्ठता का दावा करने के लिए हकदार नहीं होगा।

6. महानिदेशक के कर्तव्य—(1) महानिदेशक बल का प्रधान होगा और उसे उच्च दक्षता, प्रशिक्षण, अनुशासन और मनोबल की स्थिति में बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा तथा वह उस प्रयोजन के लिए सभी ऐसे कदम उठाएगा जो वह आवश्यक समझे जिसमें वह दौरे करके, निरीक्षण, अभिलेखों की परीक्षा करके रिपोर्ट मांग कर विनियम बनाकर अनुदेश जारी करके और बल के प्रशासन से संबंधी सभी विषयों पर अनुदेश जारी करके ऐसा करेगा। वह विशिष्टतया पर्यवेक्षक अधिकारियों का मार्गदर्शन करेगा और उन्हें निदेश देगा तथा यह सुनिश्चित करना उस का कर्तव्य होगा कि प्रत्येक पर्यवेक्षक अधिकारी उसके प्रभार में बल की दक्षता और अनुशासन को उच्च स्तर पर बनाए रखता है।

(2) महानिदेशक स्वयं को पब्लिक सेक्टर उपक्रम के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशकों और महाप्रबंधकों के साथ जोड़े रखेगा जहां बल तैनात किया गया है कि और बल के संबंध में प्रत्येक ऐसे उपक्रम की समस्याओं और आवश्यकताओं के लिए समय-समय पर स्वयं को उपलब्ध रखेगा। वह राज्य की पुलिस तथा अन्य प्राधिकारियों के साथ निकटस्थ संपर्क बनाए रखेगा ताकि पब्लिक सेक्टर उपक्रम के संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित विषयों के संबंध में राज्य पुलिस और बल के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित कर सके। वह महत्व के सभी विषयों को केन्द्रीय सरकार को सम्यक् रूप से अवगत कराएगा।

7. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सेक्टर महानिरीक्षक के कर्तव्य—(1) सम्मिलित करने के लिए अपने-अपने सेक्टरों में जो विभिन्न नियमों के अधीन यथा उपबंधित वित्तीय और प्रशासनिक विषयों में एक या अधिक जोनों से मिलकर बन सकेंगे। विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करना।

(2) क्षेत्रीय एककों में अपराध अवस्थितियों का निकटता से मॉनीटर करना और अपने-अपने सेक्टरों में उचित अपराध नियंत्रण उपायों को अपनाना।

(3) विभिन्न पब्लिक सेक्टर उपक्रमों सहित उसके प्रभार के अधीन अभिनियोजित बल का संचालन, नियंत्रण करना और अपने-अपने जोन/संयंत्र उप महा निरीक्षकों को समय के भीतर अनुदेश देना। इसके अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा, कर्तव्य/निर्वाचन कर्तव्य आदि पर अभिनियोजन भी सम्मिलित है।

(4) औद्योगिक उपक्रमों में प्रभावी, इंतजाम को सुनिश्चित करने के लिए सभी सरोकार रखने वालों का मार्गदर्शन करना तथा निदेश देना।

(5) राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक और पब्लिक सेक्टर स्थापनों के प्रधान/मुख्य कार्यपालकों के साथ संपर्क और समन्वय स्थापित करना और उसे बनाए रखना।

(6) बल मुख्यालय से परिपत्रों के अनुसार अपने सेक्टर में एककों के निरीक्षणों को कार्यान्वित करना।

(7) विभिन्न एककों से संबंधित जोन/संयंत्र महानिरीक्षकों द्वारा किए गए निरीक्षण रिपोर्ट की संवीक्षा करना और उसमें इंगित की गई कमियों के अनुपालन को मॉनीटर करना।

(8) बल मुख्यालय द्वारा जब कभी ऐसा निदेश दिया जाए सेक्टर के भीतर या अन्यत्र विशेष जांच करना।

(9) जोन/संयंत्र उप महानिरीक्षक के दौरे, कार्यक्रमों, निरीक्षण, टिप्पण और मासिक डायरियों की संवीक्षा करना और उनका अनुमोदन करना।

(10) बल के मुख्यालय द्वारा जारी किए गए नियमों/अनुदेशों के अनुसार छुट्टी प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग करना।

(11) सेक्टर के भीतर भर्ती किए गए बल के सदस्यों की तैनातियों/स्थानान्तरणों का आदेश करना।

(12) विभागीय जांच मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना और न्यायालय के मामलों की बारीकी से मॉनीटरी करना।

(13) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के देय की समय के भीतर वसूली सुनिश्चित करना।

(14) उसके प्रभाराधीन बल कार्मिक के उचित प्रशिक्षण को सुनिश्चित करना।

(15) उनके मनोबल को उच्च रखने के लिये उसके प्रभाराधीन बल कार्मिकों के कल्याण की देख-रेख करना और उसके लिए प्रभावी कदम उठाना।

(16) बल मुख्यालय द्वारा मांगी गई जानकारी/ब्यौरों के संबंध में एकको द्वारा समय के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करना।

8. उप महानिरीक्षक के कर्तव्य—(1) बल के उचित पर्यवेक्षण के लिए देश को जोनों में विभाजित किया जाएगा। एक उप महानिरीक्षक प्रत्येक जोन का भारसाधक होगा। वह उच्च दक्षता, प्रशिक्षण, अनुशासन और मनोबल की स्थिति में अपने प्रभार के बल को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रयोजन के लिए वह अपनी जोन में पब्लिक सेक्टर में औद्योगिक उपक्रमों का वर्ष में कम से कम दो बार निरीक्षण करेगा, जहां बल तैनात किया गया है और अपनी निरीक्षण रिपोर्ट बल की स्थिति और उसके प्रशासन के ब्यौरे देते हुए महानिरीक्षक को भेजेगा।

(2) उप महानिरीक्षक कमांडेंटों के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा और उनकी सहायता करेगा, सलाह देगा और उन पर नियंत्रण रखेगा। वह अपने जोन में उपक्रमों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशकों और महाप्रबंधकों के साथ मिलकर रहेगा और औद्योगिक उपक्रमों की संपत्ति के उचित संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्य पुलिस और बल के बीच पूरा सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से राज्य प्राधिकारियों के साथ भी संपर्क रखेगा। वह उप महानिरीक्षक को सभी विकासों के संबंध में पूरी तरह से अवगत करता रहेगा जिसके लिए उसे ध्यान देने की आवश्यकता है, सामान्यतः कमांडेंट और महानिरीक्षक के बीच सभी संसूचनाएं उप महा निरीक्षक के माध्यम से भेजी जाएंगी। यद्यपि अत्यावश्यक मामले में कमांडेंट महानिरीक्षक को सीधे लिख सकेगा। उस दशा में वह एक प्रति उप महानिरीक्षक को पृष्ठांकित करेगा।

9. प्रबंध निदेशक और महाप्रबंधक के कर्तव्य—किसी उपक्रम में तैनात बल उस उपक्रम के प्रबंध निदेशक के साधारण पर्यवेक्षक, निदेशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। बल का कमांडेंट सभी विकासों की पूरी सूचना प्रबंध निदेशक को देगा जिसके अंतर्गत बल की स्थिति भी है। प्रबंध निदेशक उसके उपक्रम में अवस्थित बल की चौकियों का कम से कम वर्ष में एक बार निरीक्षण करेगा।

10. कमांडेंट के कर्तव्य—(1) कमांडेंट एकक का प्रधान होगा। वह एकक की दक्षता, अनुशासन और मनोबल के लिए और उसके अधीन बल की प्रत्येक शाखा के उचित प्रबंध के लिए उत्तरदायी होगा। वह उसको कमान के अधीन बल के एककों का कालिकतः निरीक्षण करेगा। उसके अधीन बल के सभी आदेश उससे निकलेंगे और उसके अधीन बल से सभी संसूचनाएं उसके माध्यम से पारित होंगी।

(2) कमांडेंट मुख्यालय के बाहर तैनात की गई बल की टुकड़ियों का नियमित रूप से निरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे दक्षता की उचित स्थिति में रहते हैं। वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन भर्ती किए गए सभी बल-सदस्य कार्यक्रम के अनुसार बारी-बारी से परेड और पुनश्चर्चा कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। जब वह मुख्यालय में रहता है वह प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को परेड में उपस्थित रहेगा और प्रत्येक शुक्रवार को आर्डरली रूम रहेगा।

(3) कमांडेंट उस उपक्रम की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा जिसमें उसके एककों की टुकड़ी तैनात हैं। उस प्रयोजन के लिए वह जिला तथा पुलिस प्राधिकारियों और उक्त उपक्रमों में विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के साथ निकट संपर्क रखेगा। वह उक्त उपक्रम के प्रबंध निदेशक और महाप्रबंधक तथा उप महाप्रबंधक को सभी विकासों की पूरी सूचना देगा और उनको यथाविहित पाक्षिक रिपोर्टें नियमित रूप से भेजेगा। तथापि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों की यथासंभव शीघ्र साधनों द्वारा उनको सूचना देगा। वह आसूचना खंड के कार्यकरण पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देगा और सुनिश्चित करेगा कि आसूचना दक्षता से एकत्रित की जाती है और प्रबंध निदेशक, महाप्रबंधक और उप महानिरीक्षक को शीघ्रता से पहुंचाई जाती है।

11. उप कमांडेंट के कर्तव्य—(1) उप कमांडेंट उसके कर्तव्यों के निर्वहन में कमांडेंट की सहायता करेगा; और जहां वह एकक के प्रधान के रूप में रखा जाता है वह कमांडेंट के समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और केवल उन वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा जो सुसंगत नियमों के अधीन उसको प्रत्यायोजित की जाती हैं।

(2) उप कमांडेंट उसके अधीन कार्मिक की दक्षता, अनुशासन और मनोबल के लिए उत्तरदायी होगा और उपक्रम या उसको सौंपी गई उसके भाग की सुरक्षा के लिए भी उत्तरदायी होगा।

12. सहायक कमांडेंट के कर्तव्य—सहायक कमांडेंट, कमांडेंट को उसके कर्तव्यों के पालन में सहायता करेगा और जब तक उक्त प्रयोजन के लिए बनाए गए विनियमों में विशिष्टता इसके लिए निर्दिष्ट न किया जाए, वह कमांडेंट के समस्त कर्तव्यों का, जैसे और जब, वह निर्दिष्ट करे पालन करेगा। वह उसके अधीन कार्मिक की दक्षता, अनुशासन और मनोबल के लिए उत्तरदायी होगा और उपक्रम या उसको सौंपी गई उसके भाग की सुरक्षा के लिए भी उत्तरदायी होगा।

अध्याय 3

गिरफ्तारी, तलाशी आदि की प्रक्रिया

13. गिरफ्तारी—(1) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तारी करने में बल-सदस्य गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वास्तविक रूप से स्पर्श करेगा या परिरुद्ध करेगा।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति उसकी गिरफ्तारी करने के प्रयास में बलपूर्वक प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो बल का सदस्य गिरफ्तारी को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सभी साधनों का उपयोग कर सकेगा। बल प्रयोग की दशा में उस विशिष्ट अवस्थिति में उसका न्यूनतम प्रयोग किया जाना चाहिए।

(3) गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति पर उसके बचकर भागने से रोकने के लिए आवश्यकता से अधिक अवरोध नहीं किया जाएगा।

(4) गिरफ्तारी करने वाला बल-सदस्य ऐसे व्यक्ति की तलाशी कर सकेगा और सभी वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकेगा इसके अंतर्गत उसके पास पाए गए पहनने के आवश्यक कपड़े से भिन्न हथियार यदि कोई हों भी सम्मिलित हैं। सभी ऐसी वस्तुओं की एक सूची कम से कम दो प्रतिष्ठित साक्षियों की उपस्थिति में और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उपस्थिति में तैयार की जाएगी और साक्षियों और तलाशी करने वाले सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित सूची की एक प्रति, उसकी प्राप्ति की रसीद प्राप्त करने के पश्चात् इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दी जाएगी।

(5) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति तथा अभिगृहीत वस्तुओं और उसकी सूची पुलिस अधिकारी को या निकटतम पुलिस थाने में, समय तारीख और गिरफ्तारी के कारण देते हुए एक संक्षिप्त टिप्पण के साथ सौंपी जाएगी।

14. तलाशी—जब कभी भी अधिनियम की धारा 12 के अधीन किसी व्यक्ति या उसके सामान की तलाशी की जाती है तब दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में एक सूची तैयार की जाएगी और साक्षियों की ओर उस व्यक्ति द्वारा जिसने तलाशी की है सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित सूची की एक प्रति संबद्ध व्यक्ति को उसकी प्राप्ति अभिप्राप्त करने के पश्चात् दी जाएगी। ऐसी तलाशी पर इस प्रकार पाई गई संपत्ति भी उस व्यक्ति के साथ पुलिस को भेजी जाएगी। यदि ऐसी तलाशी में कुछ भी नहीं पाया जाता है तो सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित कुछ नहीं सूची विवरण उस व्यक्ति के साथ पुलिस को भेजा जाएगा।

15. विहित रैक—अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए विहित रैक हैड कांस्टेबल होगा।

अध्याय 4

बल में भर्ती

16. नियुक्ति की शक्तियाँ—अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए निरीक्षक के पद पर नियुक्ति संबद्ध उप निरीक्षक द्वारा की जाएगी और उप-महानिरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, हैड कांस्टेबल और अनुचरों के रैंकों में नियुक्ति कमांडेंट द्वारा की जाएगी।

17. बल में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें—कोई भी व्यक्ति बल में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि

(क)(i) वह भारत का नागरिक नहीं है;

(ii) वह ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्गों का नहीं है जो समय-समय पर बल में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित किए जाएं;

(ख) वह अच्छे नैतिक चरित्र का न हो;

(ग) वह केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के चिकित्सा अधिकारी या किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी या किसी सरकारी अस्पताल या औषधालय के श्रेणी एक के सहायक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रमाणित परिशिष्ट "ग" में विहित प्ररूप में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अभिप्राप्त नहीं करता है।

18. निरर्हता—वह व्यक्ति—(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, बल में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

अध्याय 5

सीधी भर्ती

19. पदों का नाम, उनका वर्गीकरण और वेतनमान—बल-सदस्यों के पदों के नाम, उनकी संख्या और वर्गीकरण तथा उनका वेतनमान वहीं होंगे जो समय-समय पर यथा संशोधित भर्ती नियमों में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

20. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं—उक्त प्रत्येक पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वही होंगी जो समय-समय पर यथा संशोधित भर्ती नियमों में विनिर्दिष्ट हैं।

21. करार—प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के आधार पर नियुक्ति के सिवाय नियुक्त किए गए प्रत्येक बल-सदस्य उसकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय परिशिष्ट "क" में विनिर्दिष्ट प्ररूप में एक करार निष्पादित करेगा।

22. कांडर—नियम 3 में उल्लिखित तीन शाखाओं में से प्रत्येक शाखा ज्येष्ठता, प्रोन्नति और पुष्टिकरण के प्रयोजन के लिए पृथक कांडर बनाएगी।

अध्याय 6

प्रतिनियुक्ति

23. (1)(क) प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा शासित होगा।

परन्तु यह कि नियम 58, नियम 59 और नियम 71 के उपबंध तक लागू नहीं होंगे।

(ख) पूर्वगामी किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक ऐसा अधिकारी बल में तत्समान रैंक को लागू अनुशासन के नियमों के अधीन रहेगा।

(2) जैसा ऊपर गया है उसके सिवाय, प्रतिनियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी उधारदाता प्राधिकारी और केन्द्रीय सरकार के बीच करार पायी जाएं।

(3) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक किसी भी समय किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति को बिना कारण बताए समाप्त कर सकेगा और ऐसी समाप्ति दंड नहीं समझी जाएगी।

अध्याय 7

प्रोन्नति

24. प्रोन्नति—इन नियमों में से किसी बात के होते हुए भी विशेष रूप से योग्य कांस्टेबल या हैड कांस्टेबल जो पंद्रह या बीस वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके हैं, यथास्थिति, हैड कांस्टेबल, या सहायक उप निरीक्षक की रैंक में उनके सेवा अभिलेखों के आधार पर उप महानिरीक्षक के अनुमोदन से कमांडेंट द्वारा प्रोन्नत किए जा सकेंगे किन्तु ऐसी प्रोन्नति की कुल संख्या ऐसे पदों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जो प्रोन्नति की पद्धति द्वारा भरी जा सकेंगी।

25. परीवीक्षा—(1) प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के सिवाय प्रत्येक बल-सदस्य भर्ती नियमों के सुसंगत स्तंभ में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए परीवीक्षा पर होगा :

परन्तु यह कि पुष्टिकरण के विनिर्दिष्ट आदेश या परीवीक्षा के समाधानप्रद समापन की घोषणा के अभाव में बल-सदस्य परीवीक्षा पर समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि कोई बल-सदस्य अपने-अपने भर्ती नियमों में विहित अवधि की दुगुनी अवधि से अधिक के लिए परीवीक्षा पर नहीं रखा जाएगा।

(2) यदि परीवीक्षा की अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय है कि बल-सदस्य स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी यथास्थिति एक मास की सूचना जारी करने के पश्चात् या ऐसी सूचना के बदले में एक मास का वेतन देने की पश्चात् उसे बल से सेवानुसृत कर सकेगा या उसे उस रैंक में प्रतिवर्तित कर सकेगा जिससे उसकी प्रोन्नति की गई थी या उसके मूल विभाग को संप्रत्यवर्तित कर सकेगा।

(3) बल-सदस्य द्वारा परीवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा किए जाने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी बल-सदस्य की उस श्रेणी में जिसमें उसने बल में पद ग्रहण किया था पुष्टिकरण वाला आदेश पारित करेगा।

26. समाप्ति—(1) जहां उप महानिरीक्षक द्वारा परीवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाओं को समाप्त करते हुए सूचना दी जाती है जिसमें परीवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाओं को या तो ऐसी सूचना की अवधि की समाप्ति पर या वेतन तथा भत्ते के संदाय द्वारा तुरंत समाप्त किया जाता है अथवा प्रारंभिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने में उसकी असफलता के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवाएं समाप्त की जाती हैं वहां महानिरीक्षक यथास्थिति यदि उक्त महानिरीक्षक या नियुक्ति प्राधिकारी जो उसके अधीनस्थ है, स्वप्रेरणा से या अन्यथा उस मामले को पुनः खोल सकेगा और ऐसी जांच करने के पश्चात् वह (i) यथास्थिति उप महानिरीक्षक या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकेगा; (ii) सूचना को वापस ले सकेगा; (iii) परीवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा में पुनः स्थापित कर सकेगा; या (iv) मामले में ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा जो वह उचित समझे :

परन्तु यह कि विशेष परिस्थितियों के सिवाय जिन्हें लेखबद्ध किया जाना चाहिए,

(क) उस दशा में जहां सूचना दी जाती है सूचना की तारीख से;

(ख) जहां कोई सूचना नहीं दी जाती है उस दशा में सेवा की समाप्ति की तारीख से;

कोई मामला तीन मास की समाप्ति के पश्चात् इस उपनियम के अधीन पुनः नहीं खोला जाएगा।

(2) जहां उपरोक्त नियम के अधीन परीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा में पुनः स्थापित किया जाता है वहां पुनः स्थापित करने के आदेश में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा : (i) परीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी सेवाओं की समाप्ति की तारीख और उसके पुनः स्थापित करने की तारीख के बीच उसकी अनुपस्थिति की अवधि के लिए संदत्त किए जाने वाले वेतन और भत्तों के अनुपात की राशि यदि कोई हो; और (ii) क्या उक्त अवधि किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए छूटी पर बिताई गई अवधि के रूप में समझी जाएगी या नहीं।

(3) जहां महानिरीक्षक ने किसी परीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए समाप्ति की है वहां ऊपर उपनियम (1) और (2) में विहित सभी शक्तियां महानिदेशक द्वारा और जहां महानिदेशक ने समाप्ति का आदेश जारी किया है वहां केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जाएगी।

अध्याय 8

विशेष उपबंध

27. व्यक्तियों के कतिपय प्रवर्गों के लिए विशेष उपबंध—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

28. शिथिल करने की शक्ति—पूर्वगामी नियमों में किसी बात के होते हुए भी, जहां बल की विरचना और उसके सम्यक् रूप से कार्यकरण के लिए ऐसा करना आवश्यक है वहां इन नियमों के अधीन (विकित्सक दृष्ट्या योग्य की अपेक्षा से भिन्न) महानिदेशक द्वारा सीधी भर्ती के समय निम्नलिखित की बाबत शिथिलीकरण किया जा सकेगा।

(i) कांस्टेबल—पात्रता का कोई मापदंड

(ii) अनुचर—केवल आयु सीमा।

अध्याय 9

सेवा की शर्तें और आचरण

29. निर्देशिकाएं—महानिदेशक, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से प्रशासन के लिए अन्य निर्देशिकाओं के साथ-साथ प्रशिक्षण निर्देशिका, स्थापन निर्देशिका की विरचना करेगा।

30. सत्यनिष्ठा का प्रतिज्ञान—नियुक्ति पर प्रत्येक रंगरूट या कैडेट से परिशिष्ट "ख" में दिए गए प्ररूप में उसकी सत्यनिष्ठा के प्रतिज्ञान की अपेक्षा की जाएगी और वह अधिनियम की धारा 6 में यथाविहित नियुक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

अध्याय 10

शास्तियां और प्रक्रिया

31. अनुशासन शासित करने वाले नियम—(1) पर्यवेक्षक अधिकारी अनुशासनिक कार्यवाहियों की बाबत तत्समान वर्ग के केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को लागू नियमों द्वारा शासित होंगे।

(2) भर्ती किए गए बल-सदस्य ऐसे मामलों में इस अध्याय के नियमों द्वारा शासित होंगे।

32. अनुशासनिक प्राधिकारी—(1) किसी विशिष्ट शास्ति को अधिरोपित करने या किसी अनुशासनिक आदेश को पारित के प्रयोजन के लिए किसी भर्ती किए गए बल-सदस्य की बाबत अनुशासनिक प्राधिकारी अनुसूची (1) में इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी होगा जिसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वह बल सदस्य सेवारत है और ऐसे प्राधिकारी से वरिष्ठ अनुसूची में उल्लिखित कोई प्राधिकारी सम्मिलित होगा।

(2) जब कभी बल सदस्य उसकी स्थायी तैनाती के स्थान से बाहर कार्य संचालन के लिए अभिनियोजित किया जाता है तब ऐसा पर्यवेक्षक अधिकारी जिसके नियंत्रण के अधीन ऐसा सदस्य इस प्रकार अभिनियोजित किया गया है उसे निलंबित करने के लिए सक्षम होगा। ऐसा पर्यवेक्षक अधिकारी उपनियम (1) में यथावर्णित उसके अनुशासनिक प्राधिकारी को उस मामले में निर्दिष्ट करेगा।

(3) नियम 34 के खंड (iv) से खंड (x) में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति के अधिरोपित करने के लिए अनुसूची (1) के अधीन सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसी किन्हीं शास्तियों को अधिरोपित करने के लिए अनुसूची (1) के अधीन सक्षम नहीं है, नियम 34 के खंड (i) से खंड (v) में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति के अधिरोपण के लिए भर्ती किए गए किसी बल सदस्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर सकेगा।

33. निलंबन—(1) नियुक्ति प्राधिकारी या कोई प्राधिकारी जिसका वह अधीनस्थ है या अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा कोई अन्य प्राधिकारी, जो राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया गया है किसी भर्ती किए गए बल-सदस्य को निम्नलिखित परिस्थितियों में निलंबित कर सकेगा।

(क) जहां उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विचारित है या लंबित है; या

(ख) जहां किसी दंडिक अपराध की बाबत उसके विरुद्ध कोई मामला अन्वेषण, जांच या विचारण अधीन है; या

(ग) जहां पूर्वोक्त प्राधिकारी की राय में राज्य की सुरक्षा के हित में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले क्रियाकलापों में वह स्वयं लगा हुआ है :

परन्तु यह कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी से निम्नतर के किसी प्राधिकारी द्वारा निलंबन का आदेश किया गया है वहां ऐसा प्राधिकारी उन परिस्थितियों के संबंध में जिनमें उसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया था नियुक्ति प्राधिकारी को तुरंत रिपोर्ट भेजेगा और उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर उसका अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा।

(2) भर्ती किया गया बल-सदस्य नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलम्बित समझा जाएगा—

(क) यदि वह अड़तालिस घंटे की अवधि से अधिक के लिए चाहे किसी दंडिक आरोप के संबंध में अथवा अन्यथा अभिरक्षा में तिरुद्ध रखा गया है, उसके निरोध की तारीख से;

(ख) अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में जिसमें वह अड़तालिस घंटे से अधिक के कारावास की अवधि के लिए दंडादिष्ट किया गया है और ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप तुरंत पदच्युत या हटाया या अनिवार्यतः सेवा निवृत्त नहीं कर दिया है, उसकी दोषसिद्धि की तारीख से :

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के खंड (ख) में निर्दिष्ट अड़तालिस घंटे की अवधि दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारंभ से संगणित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए आंतराधिक कालावधियों को, यदि कोई हों हिसाब में लिया जाएगा।

(3) जहां निलम्बित भर्ती किए गए बल-सदस्य पर सेवा से पदच्युत किए जाने, हटाये जाने या अनिवार्यतः सेवा निवृत्त किए जाने की अधिरोपित शास्ति इन नियमों के अधीन अपील या पुनर्विलोकन द्वारा अपास्त कर दी जाती है और वह मामला आगे जांच या कार्रवाई के लिए या किन्हीं अन्य निदेशों के साथ भेज दिया जाता है उसके निलंबन के आदेश को पदच्युत किए जाने, हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवा निवृत्त किए जाने के मूल आदेश की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा और अगले आदेश तक प्रवृत्त रहेगा।

(4) जहां भर्ती किए गए किसी बल-सदस्य पर अधिरोपित सेवा से पदच्युत किए जाने, हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किए जाने की शास्ति विधि के न्यायालय किसी विनिश्चय द्वारा अपास्त या प्रभावहीन घोषित कर दी जाती है और अनुशासनिक प्राधिकारी के मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् उन अभिकथनों के आधार पर जिन पर पदच्युत किए जाने हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किए जाने की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गई थी उसके विरुद्ध आगे जांच करने का विनिश्चय करता है वहां भर्ती किया गया बल-सदस्य पदच्युत किए जाने, हटाये जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किए जाने के मूल आदेश की तारीख से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलंबन, निलंबनाधीन रखा गया समझा जाएगा और अगले आदेश होने तक निलंबित बना रहेगा।

(5) (क) इस नियम के अधीन किया गया या समझा गया निलंबन का कोई आदेश उस प्राधिकारी द्वारा जो ऐसा करने के लिए सक्षम है उपांतरित या प्रतिसंवृत्त किए जाने तक प्रवृत्त बना रहेगा।

(ख) जहां भर्ती किया गया कोई बल-सदस्य निलंबित कर दिया गया है या निलंबित किया गया समझा गया है (चाहे किन्हीं अनुशासनिक कार्यवाहियों के संबंध में या अन्यथा) और कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही उस निलंबन के बने रहने के दौरान उसके विरुद्ध आरंभ हो जाती है वहां उसे निलंबित करने के सक्षम प्राधिकारी कारणों को लेखबद्ध करके यह निदेश दे सकेगा कि भर्ती किया गया बल-सदस्य ऐसी सभी कार्यवाहियों या किसी एक कार्यवाही की समाप्ति तक निलंबित बना रहेगा।

(ग) इस नियम के अधीन किया गया या किया गया समझा गया निलंबन का आदेश उस प्राधिकारी द्वारा जिसने उस आदेश को किया है या किया गया समझा गया है या किसी प्राधिकारी द्वारा जिसका वह प्राधिकारी अधीनस्थ है किसी भी समय उपांतरित या प्रतिसंवृत्त किया जा सकेगा।

34. शास्तियों की प्रकृति—निम्नलिखित शास्तियां ठीक और पर्याप्त कारणों के लिए और जैसा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित है उसके अनुसार भर्ती किए गए किसी बल-सदस्य पर अधिरोपित की जा सकेगी, अर्थात् :-

गंभीर शास्तियां—

(i) सेवा से पदच्युत किया जाना जो आमतौर से सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए एक निरर्हता होगी;

(ii) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी;

(iii) अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति;

(iv) निम्नतर समय वेतनमान, श्रेणी, पद या सेवा में अवनति जो सरकारी सेवक की उस समय वेतनमान श्रेणी पद या सेवा के लिए आमतौर से वर्जन होगी जिससे उसकी उस श्रेणी या पद या सेवा में पुनः स्थापन की शर्तों के संबंध में आगे निदेशों के साथ या बिना अवनति की गई थी जिससे भर्ती किए गए बल-सदस्य और उस श्रेणी, पद या सेवा में ऐसे पुनः स्थापन पर उसकी ज्येष्ठता और वेतन की अवनति की गई थी।

(v) नीचे खंड (viii) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समय वेतनमान में निरन्तर प्रक्रम पर अवनति जिसमें आगे यह निदेश होगा कि भर्ती किया गया सदस्य ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन की वृद्धियां उपार्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर वह अवनति उसके वेतन की भविष्य में वृद्धियों को मुलतवी करने में प्रभावी होगी।

छोटी शास्तियां—

- (vi) परिनिंदा;
- (vii) उसकी प्रोन्नति को रोकना;
- (viii) बिना संचयी प्रभाव और उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति;
- (ix) वेतन वृद्धि रोकना;
- (x) 7 दिन के वेतन से अनधिक की किसी राशि के लिए जुर्माना।

स्पष्टीकरण—इस नियम के अर्थान्तर्गत निम्नलिखित शास्तियां की कोटि में नहीं आएंगी, अर्थात्—

(क) उसकी नियुक्ति के नियमों या आदेशों या निबंधनों के अनुसार विभागीय परीक्षा में असफलता के लिए किसी भर्ती किए गए सदस्य की वेतन वृद्धि को रोकना;

(ख) वर्जन पार करने के लिए उसकी आयोग्यता के आधार पर समय वेतनमान में दक्षतारोध पर किसी भर्ती किए गए सदस्य की वेतन वृद्धि को रोका जाना;

(ग) किसी रैंक या पद पर प्रोन्नति के लिए जिसके लिए वह पात्र है उसके मामले पर विचार करने के पश्चात् किसी अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत से भर्ती किए गए सदस्य की प्रोन्नति न होना;

(घ) किसी उच्चतर रैंक या पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले भर्ती किए गए सदस्य का इस आधार पर कि ऐसे उच्चतर रैंक या पद के लिए उसे विचारण के पश्चात् अनुपयुक्त समझा गया है या उसके आचरण से असंबद्ध किन्ही प्रशासनिक आधारों पर निम्नतर रैंक या पद पर प्रतिवर्तन;

(ङ.) उसकी नियुक्ति या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के निबंधनों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर किसी अन्य रैंक या पद पर परिवीक्षा पर नियुक्ति किए गए किसी भर्ती किए गए सदस्य का परिवर्तन;

(च) भर्ती किए गए किसी सदस्य की सेवाओं का प्रतिस्थापन जिनकी सेवाएं केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी प्राधिकरण से ली गई थीं, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उक्त प्राधिकरण की सुविधा पर ऐसी जिससे भर्ती किए गए ऐसे सदस्य की सेवाएं ली गई थीं;

(छ) उसकी अधिवार्षिता या सेवा निवृत्ति से संबंधित उपबंधों के अनुसार भर्ती किए गए सदस्य की अधिवार्षिता; सेवा निवृत्ति;

(ज) निम्नलिखित की सेवाओं की समाप्ति—

(i) उसकी नियुक्ति के निबंधनों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार उसकी परीक्षा का प्रारंभ के दौरान या उसकी समाप्ति पर परिवीक्षा पर नियुक्ति किए गए सदस्य की सेवाओं की समाप्ति; या

(ii) नियम 25 के उपबंधों के अनुसार भर्ती किए गए अस्थायी सदस्य की सेवा की समाप्ति;

(iii) ऐसे करार के निबंधनों के अनुसार किसी करार के अधीन नियोजित भर्ती किए गए सदस्यों की सेवा की समाप्ति;

(झ) नियम 55 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित "अकार्यदिन" के रूप में कर्तव्य से अनुपस्थित सम्पत्ति।

35. **क्षुद्र दंड**—हैड कांस्टेबल, कांस्टेबल और अनुचर को चौदह दिन से अनधिक की कालावधि के लिए अतिरिक्त कष्टकर पण्ड ड्यूटी फटीग या अन्य ड्यूटी भी दंड के रूप में प्रदान की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण—क्षुद्र दंड आमतौर से इस अध्याय के नियम 38 में यथाउपस्थित आर्डरली रूप में दिए जाएंगे।

36. **बड़ी शास्तियों को अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया**—(1) लोकसेवक (जांच) अधिनियम 1950, (1950 च. 27) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियम 34 के खंड (i) से (v) में यथाविनिर्दिष्ट कोई शास्ति किसी भर्ती किए गए बल-सदस्य पर अधिरोपित करने वाला कोई आदेश सिवाय इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में जहां तक हो सके की गई जांच के पश्चात् के सिवाय नहीं किया जाएगा।

जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि भर्ती किए गए किसी बल-सदस्य के विरुद्ध अवचर या कदाचर किसी शास्ति को सत्यता की जांच के लिए आधार है तब वह स्वयं उसकी जांच कर सके या उसकी सत्यता की जांच के लिए कोई प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—जहां अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच करता है वहां इस नियम के उपनियम (7) से उपनियम (12) में किसी निर्देश का अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा।

(3) जहाँ इस नियम के अधीन भर्ती किए गए किसी बल-सदस्य के विरुद्ध जांच करने की प्रस्थापना की जाती है वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी निम्नलिखित लेखबद्ध करेगा या लेखबद्ध करवाएगा—

- (i) निश्चित और सुस्पष्ट आरोप की मदों में अवचार या कदाचार के लांछन का सार;
- (ii) प्रत्येक आरोप की मद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछन का विवरण जिसमें निम्नलिखित हो; या
- (क) भर्ती किए गए बल-सदस्य द्वारा की गई किसी स्वीकृति या संस्वीकृति सहित सभी सुसंगत तथ्यों का कथन;
- (ख) दस्तावेजों की सूची जिसके द्वारा और साक्षियों की सूची जिनके द्वारा आरोप की मदों की सिद्धि किए जाने की प्रस्थापना की जाती है।

(4) अनुशासनिक प्राधिकारी भर्ती किए गए बल-सदस्य को आरोप की मदों, अवचार या कदाचार के लांछनों के कथन और दस्तावेज तथा साक्षियों की सूची जिसके द्वारा प्रत्येक आरोप की मद सिद्ध की जानी है, की एक परिदत्त प्रदत्त करेगा या परिदत्त करवाएगा और भर्ती किए गए बल-सदस्य से ऐसे समय के भीतर जो विनिश्चित किया जाए उसकी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा और यह कथन करने के लिए कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुनवाई किए जाने की वांछा करता है या नहीं।

(5) (क) प्रतिरक्षा के लिखित कथन की प्राप्ति पर अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं ऐसे आरोप की मदों की जांच कर सकेगा जो स्वीकृत नहीं की गई हैं या यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है तो उपनियम (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए जांच प्राधिकारी को नियुक्त कर सकेगा जो निरीक्षक की रैंक से नीचे का न हो और जहाँ प्रतिरक्षा के उसके लिखित कथन में भर्ती किए गए बल-सदस्य द्वारा सभी आरोपों की मदें स्वीकृत कर ली गई हैं वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसे साक्ष्य लेने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और उपनियम (20) से उपनियम (22) में अधिकथित रीति से आदेश पारित करेगा।

(ख) यदि भर्ती किए गए बल-सदस्य द्वारा कोई प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप की मदों की स्वयं जांच करेगा या वह ऐसा करना आवश्यक समझता है तो इस प्रयोजन के लिए उपनियम (2) के अधीन कोई जांच प्राधिकारी नियुक्त करेगा।

(6) अनुशासनिक प्राधिकारी जहाँ वह जांच प्राधिकारी नहीं है जांच प्राधिकारी को निम्नलिखित भेजेगा:

- (i) आरोप की मदों की और अवचार या कदाचार के लांछनों के कथन की एक प्रति;
- (ii) भर्ती किए गए बल-सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिरक्षा के लिखित कथन, यदि कोई हो, की एक प्रति;
- (iii) उपनियम (3) में निर्दिष्ट साक्षियों के कथन, यदि कोई हों, की एक प्रति;
- (iv) भर्ती किए गये बल-सदस्य को उपनियम (3) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के परिदान को साबित करने वाला साक्ष्य;

(7) भर्ती किया गया बल-सदस्य आरोप की मदों की और अवचार या कदाचार के लांछन के कथन की उसके द्वारा प्राप्ति की तारीख से दस कार्यकरण के दिनों के भीतर ऐसी तारीख और ऐसे समय और स्थान पर जो जांच प्राधिकारी इस निमित्त लिखित सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे या आगे के दस दिन से अनधिक के समय के भीतर जो जांच प्राधिकारी अनुज्ञात करे जांच प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से हाजिर होगा।

(8) (क) इस प्रकार आरोपित भर्ती किया गया बल-सदस्य जांच के स्थान पर तैनात किसी अन्य बल-सदस्य की सहायता से अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए जांच प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा। उसकी प्रतिरक्षा सहायता के लिए वह तीन विकल्प देगा और नियंत्रण अधिकारी उसके द्वारा उपदर्शित किए गए तीन में किसी एक को प्रतिनियुक्त करेगा;

(ख) भर्ती किए गए बल-सदस्य एक साथ तीन से अधिक मामलों को हाथ में नहीं ले सकेगा जिसमें वह प्रतिरक्षा सहायता दे रहा हो। तथापि, ऐसे व्यक्तियों के नियंत्रण प्राधिकारी जिससे सहायता लेने की वांछा की जाती है यदि लोकहित की ऐसी मांग है तो प्रतिरक्षा सहायक के रूप में उसके कार्यकरण के लिए अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेगा।

(9) यदि भर्ती किया गया बल-सदस्य जिसने प्रतिरक्षा के अपने लिखित कथन में आरोप की किसी मद को स्वीकार नहीं किया है या प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया है जांच प्राधिकारी के समक्ष हाजिर होता है, ऐसा प्राधिकारी उससे यह पूछेगा कि क्या वह दोषी है या प्रतिरक्षा के लिए कुछ कहेगा और यदि वह आरोप की किसी मद का दोषी होने का अभिवचन करता है, जांच प्राधिकारी अभिवाक अभिलिखित करेगा, अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर भर्ती किए गए बल-सदस्य के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा।

(10) जांच प्राधिकारी आरोप की उन मदों से संबंधित निष्कर्ष को लौटा देगा जिसके संबंध में भर्ती किया गया बल-सदस्य दोषी होने का अभिवचन करता है।

(11) जांच प्राधिकारी दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश किए जाने के लिए सूचना की प्राप्ति पर उसे या उसकी प्रतियों को उस प्राधिकारी को जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज रखे हैं अर्पित करेगा जिसके साथ ऐसी अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट ऐसी तारीख तक दस्तावेजों के प्रकटीकरण के लिए अध्यपेक्षा होगी।

(12) उपनियम (11) में निर्दिष्ट अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर प्रत्येक अध्यपेक्षा किए गए दस्तावेजों की अभिरक्षा या कब्जे वाला प्रत्येक अधिकारी जांच प्राधिकारी के समक्ष उसे प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यह कि यदि अध्यपेक्षित दस्तावेजों की अभिरक्षा या कब्जे वाले प्राधिकारी का ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे यह समाधान हो जाता है कि ऐसे सभी या किसी एक दस्तावेज का प्रकटीकरण लोकहित या राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध होगा वह तदनुसार जांच प्राधिकारी को इसकी जानकारी देगा और जांच प्राधिकारी ऐसी जानकारी मिलने पर उस सूचना को भर्ती किए गए बल-सदस्य को सूचित करेगा और उसके द्वारा दस्तावेजों के पेश किए जाने या प्रकटीकरण के लिए की गई अध्यपेक्षा को वापस लेगा।

(13) जांच प्राधिकारी भर्ती किए गए बल-सदस्य को यदि वह ऐसा उसकी प्रतिरक्षा तैयार करने के प्रयोजन के लिए ऐसा चाहता है तो ऐसे आदेश की तारीख से 5 दिन के भीतर उपनियम (3) में निर्दिष्ट सूची में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे शासकीय अभिलेखों का निरीक्षण करने और उनका उद्धरण लेने के लिए निदेश दे सकेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसे दस्तावेजों की पहुंच स्वीकृत करने के लिए इंकार कर सकेगा यदि उस प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे ऐसे अभिलेख के प्रयोजन के लिए सुसंगत नहीं हैं या ये लोकहित के विरुद्ध हैं।

(14) जांच प्राधिकारी, यदि भर्ती किया गया बल-सदस्य विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होने में असफल रहता है या इंकार करता है या अभिवचन करने से बचता है तो ऐसे साक्ष्य को अभिलिखित करने के लिए अग्रसर होगा जिसके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध किया जाना है।

(15) जांच के लिए नियत तारीख पर जांच प्राधिकारी मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की परीक्षा करेगा जिसके द्वारा आरोप की मदों को साबित किया जाना प्रस्थापित है। भर्ती किया गया बल-सदस्य आरोप के समर्थन में परीक्षित साक्ष्यों की प्रतिपरीक्षा करने का हकदार होगा। जांच प्राधिकारी साक्ष्यों को ऐसे प्रश्न भी कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(16) भर्ती किया गया बल-सदस्य अपने प्रतिरक्षा साक्ष्यों के नाम दे सकेगा जिनकी परीक्षा की जाएगी। यदि जांच प्राधिकारी किसी प्रतिरक्षा साक्षी की इस आधार पर परीक्षा करने से इंकार करता है कि उसका साक्ष्य सुसंगत या तात्त्विक नहीं है, तो उसके लिए वह कारणों को लेखबद्ध करेगा।

(17) जांच प्राधिकारी भर्ती किए गए बल-सदस्य के अपने मामले के खन्द करने के पश्चात् और साधारणतया उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपस्थित किन्हीं परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य में उसके विरुद्ध उपस्थित किन्हीं परिस्थितियों पर उससे प्रश्न करेगा। भर्ती किए गए सदस्य को यदि वह ऐसा चाहता है तो 7 दिन के भीतर उसकी प्रतिरक्षा के लिखित कथन को फाइल करने के लिए भी अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(18) यदि भर्ती किए गए सदस्य को जिसको आरोप की मदों की एक प्रति प्रदत्त की गई है उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व लिखित कथन प्रस्तुत नहीं करता है या जांच प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता है या नियम के उपबंधों की पालना करने से इंकार करता है तो जांच प्राधिकारी एकपक्षीय रूप से जांच कर सकेगा।

(19)(i) जांच की समाप्ति के पश्चात् एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होगा—

(क) आरोप की मद और अवचार या कदाचार के लांछन का कथन;

(ख) आरोप की प्रत्येक मद की बाबत भर्ती किए गए बल-सदस्य की प्रतिरक्षा;

(ग) आरोप की प्रत्येक मद की बाबत साक्ष्य का निर्धारण;

(घ) आरोप की प्रत्येक मद के संबंध में निष्कर्ष और उसके कारण—

स्पष्टीकरण - यदि जांच प्राधिकारी की राय में जांच की कार्यवाहियों से आरोप की मूल मद से भिन्न आरोप की कोई मद सिद्ध होती है तो वह आरोप की ऐसी मद के संबंध में अपने निष्कर्षों का अभिलेख कर सकेगा :

परन्तु यह आरोप की ऐसी मद के संबंध में निष्कर्षों को अभिलिखित नहीं किया जाएगा जब तक कि भर्ती किए गए बल-सदस्य ने या तो उस तथ्य को जिस पर आरोप की ऐसी मद आधारित है स्वीकार नहीं किया है या उसको आरोप की ऐसी मद के विरुद्ध स्वयं की प्रतिरक्षा का उचित अवसर नहीं मिला है।

(ii) जांच प्राधिकारी जहां वह स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है वहां जांच के अभिलेखों को अनुशासनिक प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित होगा—

(क) खंड (i) के अधीन उसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट;

(ख) भर्ती किए गए सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिरक्षा का लिखित कथन, यदि कोई हो;

(ग) जांच के अनुक्रम में पेश की गई मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य ;

(घ) जांच के अनुक्रम के दौरान भर्ती किए गए सदस्य द्वारा फाइल किया गया लिखित पक्षसार यदि कोई हो;

(ङ) जांच के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी और जांच प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश यदि कोई हो।

(20) (i) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी कोई छोटी शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम है और नियम 34 में विनिर्दिष्ट बड़ी शास्तियों में से किसी शास्ति को अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं है उसने किसी आरोप की मर्दों की जांच स्वयं की है या जांच करवाई है और वह प्राधिकारी अपनी स्वयं के निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए या उसके द्वारा नियुक्त किसी जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों में से किसी निष्कर्ष के संबंध में उसके विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए उसकी यह राय है कि नियम 34 में विनिर्दिष्ट बड़ी शास्ति भर्ती किए गए सदस्य पर अधिरोपित की जानी चाहिए वहां वह प्राधिकारी जांच के अभिलेखों को ऐसे अनुशासनिक प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा जो बड़ी शास्तियों में से किसी शास्ति को अधिरोपित करने के लिए सक्षम है।

(ii) अनुशासनिक प्राधिकारी जिसको अभिलेख इस प्रकार अग्रेषित किए जाते हैं अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर सकेगा या यथास्थिति, उस अनुशासनिक प्राधिकारी या जांच प्राधिकारी को विप्रेषित कर सकेगा जिससे अभिलेख अग्रेषित किया गया था या उस जांच प्राधिकारी को किसी बिन्दु पर आगे जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए भेजेगा।

(21) (i) अनुशासनिक प्राधिकारी यदि वह स्वयं जांच प्राधिकारी नहीं है जांच के अभिलेखों पर विचार कर सकेगा और प्रत्येक आरोप पर उसके निष्कर्षों के अभिलिखित करेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी उसके द्वारा अभिलिखित किए गए कारणों से जांच प्राधिकारी को आगे जांच और रिपोर्ट के लिए उस मामले को विप्रेषित करेगा और जांच प्राधिकारी जहां तक हो सके इस नियम के उपबंधों के अनुसार आगे जांच करने के लिए उस पर अग्रसर होगा।

(ii) अनुशासनिक प्राधिकारी यदि आरोप के किसी मद पर जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमत है तो ऐसी असहमति के लिए उसके कारणों को अभिलिखित करेगा और उक्त प्रयोजन के लिए अभिलेख पर साक्ष्य पर्याप्त है तो ऐसे आरोप पर अपने स्वयं के निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(22) (i) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की, आरोप की सभी या किसी मद पर उसके निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि नियम 34 में विनिर्दिष्ट किसी लघु शास्ति भर्ती किए गए सदस्य पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह नियम 37 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी शास्ति को अधिरोपित करने का आदेश करेगा ;

(ii) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की आरोप की सभी या किसी मद पर उसके निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए और जांच के अनुक्रम के दौरान दी गई साक्ष्य के आधार पर यह राय है कि नियम 34 में विनिर्दिष्ट बड़ी शास्तियों में से कोई शास्ति भर्ती किए गए सदस्य पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह ऐसी शास्ति आदेश करने का आदेश करेगा और यह आवश्यक नहीं होगा कि भर्ती किए गए सदस्य के अधिरोपित किए जाने के लिए प्रस्थापित शास्ति पर अभ्यावेद करने का कोई अवसर दिया जाए।

37. छोटी शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया.—(1) नियम 34 में विनिर्दिष्ट किसी छोटी शास्ति को अधिरोपित करने का कोई आदेश निम्नलिखित के पश्चात् ही किया जाएगा—

(क) अवचार या कदाचार के लांछनों की लिखित में भर्ती किए गए सदस्य को सूचना देने जिनपर उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रस्थापना की जाती है और ऐसा अभ्यावेदन करने का उचित अवसर देगा जो वह प्रस्ताव के विरुद्ध करना चाहता है ;

(ख) नियम 36 के उपनियम (3) से (22) में अधिकथित रीति में यदि अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसा चाहता है जांच करने ;

(ग) खंड (क) के अधीन भर्ती किए गए सदस्य द्वारा पेश किया गया अभ्यावेदन यदि कोई हो, को लेने और खंड (ख) के अधीन की गई जांच का अभिलेख यदि कोई हो, पर विचार करने ; और

(घ) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन पर निष्कर्षों के अभिलिखित करने ;

(2) उपनियम (1) के खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, यदि उस उपनियम के खंड (क) के अधीन सरकारी सेवक द्वारा किए गए अभ्यावेदन यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् यह प्रस्थापना की जाती है कि वेतन की वृद्धियां रोकी जाएं और ऐसी वेतन वृद्धियों के रोके जाने से सरकारी सेवक को संदेय पेंशन की राशि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या 3 साल से अधिक की अवधि के लिए वेतन की वृद्धियां रोकी जाएं या किसी अवधि के लिए संचयी प्रभाव के साथ वेतन की वृद्धियां रोकी जाएं तो किसी ऐसी शास्ति को भर्ती किए गए बल-सदस्य पर अधिरोपित करने का कोई आदेश को करने से पूर्व नियम 36 के उपनियम (3) से उपनियम (22) में अधिकथित रीति में जांच की जाएगी।

(3) ऐसे मामलों में कार्यवाहियों के अभिलेखों के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे—(i) उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के प्रस्ताव की इस प्रकार आरोप आरोपित भर्ती किए गए सदस्य को सूचना की एक प्रति;

(ii) उसको प्रदत्त की गई अवचार या कदाचार के लांछन के कथन की एक प्रति;

(iii) उसका अभ्यावेदन यदि कोई हो;

(iv) जांच के दौरान पेश किया गया साक्ष्य यदि कोई है ;

(v) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन पर निष्कर्ष ;

(vi) प्रत्येक मामले के संबंध में उसके कारणों के साथ आदेश।

38. **क्षुद्र दंड अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया-भर्ती किए गए ऐसे बल-सदस्य**—जो हैड कांस्टेबल के रैंक से ऊंची रैंक के नहीं हैं द्वारा क्षुद्र अनुशासन और हल्के अवचार के मामलों के संबंध में आर्डरली रुम में जांच की जाएगी और उन्हें निपटाया जाएगा। नियम 35 में वर्णित दंड आर्डरली रुम रजिस्टर में जो ऐसे दंडों को अभिलेख रखने के लिए रखे जाएंगे संक्षिप्त कार्यवाहियों का अभिलेख करने के पश्चात् प्रदान किए जा सकेंगे। आर्डरली रुम में दिए गए दंड के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

39. **कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया**—नियम 36 से नियम 38 में किसी बात के होते हुए भी—

(i) जहां कोई शास्ति आचरण के ऐसे आधार पर भर्ती किए गए किसी बल-सदस्य पर अधिरोपित की जाती है जिसके परिणामस्वरूप किसी अपराधिक आरोप पर उसकी दोष सिद्ध हुई है ; या

(ii) जांच अनुशासनिक प्राधिकारी का, ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों में उपबंधित रीति में जांच करना युक्तियुक्त तौर पर साध्य नहीं है ; या

(ii) जहां राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि राज्यों की सुरक्षा के हित में इन नियमों में उपबंधित रीति में कोई जांच करना समीचीन नहीं है वहां अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा और उनके आधार पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे;

परंतु यह कि भर्ती किए गए बल-सदस्य को खंड (i) के अधीन मामले में कोई आदेश किए जाने के पूर्व अधिरोपित करने के लिए प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जा सकेगा।

40. **राज्य सरकारें आदि से उधार लिए गए भर्ती किए गए बल-सदस्यों के संबंध में उपबंध**—(1) जहां निलंबन का आदेश किया जाता है या भर्ती किए गए बल-सदस्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों की जाती हैं जिसकी सेवाएं केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से या राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ प्राधिकरण से उधार ली गई हैं वहां उसकी सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकरण को (जिसे इसके पश्चात् इन नियमों में "उधार देने वाला प्राधिकरण" कहा गया है) तुरंत यथास्थिति, भर्ती किए गए बल-सदस्य के निलंबन के आदेश की परिस्थितियों या अनुशासनिक कार्यवाहियों के प्रारंभ के संबंध में सूचित किया जाएगा।

(2) ऐसे भर्ती किए गए बल-सदस्य के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाहियों में निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि नियम 34 के खंड (vi) से (x) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति उस पर अधिरोपित की जानी चाहिए वह नियम 36 के उपनियम 22 (i) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उधार दाता प्राधिकरण से परामर्श के पश्चात् उस मामले के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे—

(i) परंतु उधार लेने वाले प्राधिकरण और उधार देने वाले प्राधिकरण के बीच मतभेद की दशा में ऐसे भर्ती किए गए बल-सदस्य की सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकरण की सुपुर्दगी पर प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

(ii) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि नियम 34 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति ऐसे बल-सदस्य पर अधिरोपित की जानी चाहिए तब वह उधार देने वाले प्राधिकरण की सुपुर्दगी पर ऐसे बल-सदस्य की सेवाओं को प्रतिस्थापित करेगा और ऐसी कार्यवाई के लिए जो वह आवश्यक समझे जांच की कार्यवाहियों को उसको भेजेगा।

41. **राज्य सरकार आदि को उधार दिए गए भर्ती किए गए बल-सदस्य के संबंध में उपबंध**—(1) जहां किसी भर्ती किए गए बल-सदस्य की सेवाएं केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग या राज्य सरकार को या अन्य प्राधिकरण जिसे इसमें इसके पश्चात् इस नियम में "उधार लेने वाला प्राधिकरण" कहा गया है को उधार दी जाती हैं वहां उधार लेने वाले प्राधिकरण को ऐसे भर्ती किए गए बल-सदस्य को निलंबित करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी की और उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्तियां प्राप्त होंगी ;

परंतु यह कि उधार लेने वाला प्राधिकरण उस प्राधिकरण को जिसने भर्ती किए गए बल-सदस्य की सेवाएं उधार दी हैं जिसे इसमें इसके पश्चात् इस नियम में "उधार देने वाला प्राधिकरण" कहा गया है को यथास्थिति उन परिस्थितियों की उसके फलस्वरूप ऐसे भर्ती किए गए बल-सदस्य के निलंबन का आदेश हुआ है या अनुशासनिक कार्यवाहियों के प्रारंभ की तुरंत सूचना देगा।

(2) भर्ती किए गए बल-सदस्य के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाहियों में निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए ;—

(i) यदि उधार लेने वाले प्राधिकरण की यह राय है कि नियम 34 के खंड (vi) से (x) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति ऐसे सदस्य पर अधिरोपित की जानी चाहिए तब वह उधारदाता प्राधिकरण से परामर्श के पश्चात् उस मामले के संबंध में ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे;

परंतु उधार लेने वाले प्राधिकरण और उधार देने वाले प्राधिकरण के बीच मतभेद की दशा में ऐसे भर्ती किए गए बल-सदस्य की सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकरण की सुपुर्दगी में प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(ii) यदि उधार लेने वाले प्राधिकरण की यह राय है कि नियम 34 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति भर्ती किए गए बल-सदस्य पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह उधार देने वाले प्राधिकरण की सुपुर्दगी में उसकी सेवाओं को प्रतिस्थापित करेगा और जांच की कार्यवाहियों को पारेषित करेगा और उसके पश्चात् उधार लेने वाला प्राधिकरण यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी है तो उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो आवश्यक समझे ;

परंतु यह कि किसी ऐसे आदेश के पारित करने के पूर्व अनुशासनिक प्राधिकरण नियम 36 के उपनियम (22) के उपबंधों की अनुपालना करेगा।

स्पष्टीकरण—अनुशासनिक प्राधिकरण उधार लेने वाले प्राधिकारी द्वारा उसको पारेषित जांच के अभिलेख पर इस खंड के अधीन कोई आदेश कर सकेगा या नियम 36 के अनुसार जहां तक हो सके जैसा वह आवश्यक समझे आगे ऐसी जांच करने के पश्चात् आदेश कर सकेगा।

42. रैंक आदि में अवनति.—भर्ती किए गए किसी बल-सदस्य को उस रैंक से नीचे की रैंक में अवनत नहीं किया जाएगा जिसमें उसकी सेवा में प्रथम नियुक्ति हुई थी न ही उसे इस अर्थ में स्थायी रूप से अवनत किया जाएगा कि वह यदि उसकी पश्चात्पूर्वी सेवा कितनी ही सराहनीय रही हो पुनः प्रोन्नति के लिए कभी पात्र नहीं हो सकेगा। जब किसी निम्नतर रैंक वर्ग, श्रेणी या किसी निम्नतर समय मापमान या उस समय मापमान में किसी निम्नतर प्रक्रम अवनति का आदेश किया जाता है तब आदेश में ऐसी अवनति पर निम्नतर रैंक में स्थिति तथा वह अवधि जिसके लिए अवनति प्रभावी होती है भी विनिर्दिष्ट होगी।

43. वेतन वृद्धि का रोका जाना.—दंड के रूप में वेतन वृद्धि रोकने की दशा में आदेश उस अवधि का कथन करेगा जिसके लिए वेतन वृद्धि रोकी गई है और क्या उसका आगे वेतन वृद्धि रोकने का प्रभाव होगा या नहीं।

धारा-11

अपील, पुनरीक्षण और आवेदन

44. निलंबन के आदेश के विरुद्ध अपील.—भर्ती किया गया कोई बल-सदस्य निलंबन के आदेश के विरुद्ध उस प्राधिकरण को अपील कर सकेगा जिसकी वह प्राधिकरण जिसने वह आदेश किया है या किया गया समझा गया है सीधे अधीन है।

45. आदेश जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी.—इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी—

(i) अंतरवर्ती प्रकृति का या सहायक कदम की प्रकृति का या निलंबन के आदेश से भिन्न अनुशासनिक कार्यवाहियों के निपटान का कोई आदेश ; और

(ii) नियम 36 के अधीन जांच के क्रम में जांच प्राधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश।

46. शास्तियां अधिरोपित करने के आदेश के विरुद्ध अपील.—(1) भर्ती किया गया सदस्य निम्नलिखित सभी या किसी आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा अर्थात् :—

(i) नियम 33 के अधीन किया गया या किया गया समझा गया निलंबन का आदेश ;

(ii) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा या किसी अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा किया गया नियम 34 में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति को अधिरोपित करने वाला आदेश।

(2) ऐसी अपील उस प्राधिकारी से अव्यवहित वरिष्ठ प्राधिकारी को की जाएगी जिसने वह शास्ति अधिरोपित की है।

टिप्पण : (i) उप महानिरीक्षक के आदेश के विरुद्ध अपील सेक्टर महानिरीक्षक को और सेक्टर महानिरीक्षक के आदेश के विरुद्ध महानिदेशक को होगी।

(ii) बल मुख्यालय पर जिसके अंतर्गत उप महानिरीक्षक (प्रशिक्षण और अग्नि शमन) भी है, के आदेश के विरुद्ध अपील महानिरीक्षक (मुख्यालय) के आदेश के विरुद्ध महानिदेशक को होगी।

(iii) महानिदेशक के आदेश के विरुद्ध अपील केन्द्रीय सरकार को होगी।

(iv) जहां वह व्यक्ति जिसने वह आदेश किया है जिसकी अपील की गई है उसकी पश्चात्पूर्वी नियुक्ति के कारण या अन्यथा ऐसे आदेश की जांच की बाबत अपील प्राधिकारी बन जाता है वहां ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को होगी। जिसका ऐसा व्यक्ति अव्यवहित अधीनस्थ है।

(3) कोई दूसरी अपील नहीं होगी.—किन्तु जब अपील प्राधिकारी जिसके विरुद्ध अपील की गई है उस शास्ति से उच्चतर शास्ति अधिरोपित करता है तब उस अपील प्राधिकारी से ठीक वरिष्ठ प्राधिकारी को अपील होगी।

47. **अपील के लिए परिसीमा की अवधि.**—इन नियमों के अधीन कोई अपील ग्रहण की जाएगी जब तक कि वह उस तारीख से जिसको अपीलार्थी उस आदेश की प्रति प्राप्त करता है जिसके विरुद्ध अपील की गई है, 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है।

परंतु अपील प्राधिकारी उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी का समय के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।

48. **अपील का प्ररूप और अंतरवस्तु.**—(1) अपील प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक भर्ती किया गया बल-सदस्य अपने स्वयं के नाम से पृथक् रूप से अपील कर सकेगा।

(2) अपील उस प्राधिकारी को संबोधित की जाएगी जिसको अपील की जाती है जिसमें वे सभी तात्त्विक कथन और तर्क होंगे जिन पर अपीलार्थी निर्भर करता है तथा उसमें कोई अनादर पूर्ण या अनुचित भाषा नहीं होगी और वह स्वयं में पूर्ण होगा।

49. **अपील का पेश किया जाना.**—(1) अपीलार्थी ऐसी अपील को उस प्राधिकारी को पेश करेगा जिसने वह आदेश किया था जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है :

परंतु यह कि यदि अपीलार्थी ऐसी अपील के पेश करने के समय उस प्राधिकारी के अधीन सेवारत नहीं है तब उस अपील को उस प्राधिकारी को पेश करेगा जिसके अधीन वह सेवारत है और वह प्राधिकारी उसे तुरंत समुचित प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। यदि अपीलार्थी सेवा में नहीं है तो वह उसकी अपील को सीधे अपील प्राधिकारी को पेश करेगा और अपील की एक प्रति अपीलार्थी द्वारा उस प्राधिकारी को भी अग्रेषित की जाएगी जिसने वह आदेश किया था जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

50. **अपीलों का रोका जाना.**—(1) वह प्राधिकारी जिसने वह आदेश किया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है अपील को रोक सकेगा यदि—(i) यह ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील है जिसके विरुद्ध नियम 45 के अधीन कोई अपील नहीं होती है ; या

(ii) यह नियम 48 के अधीन के अनुरूप नहीं है ; या

(iii) यह नियम 47 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पेश नहीं की गई है और विलंब के लिए पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया गया है ; या

(iv) यह पहले से विनिश्चित किसी अपील की पुनरावृत्ति है और परिस्थितियों के कोई नए तथ्य नहीं दिए गए हैं ;

परंतु यह कि कोई अपील केवल इस आधार पर रोकी गई है कि वह नियम 48 के उपबंधों के अनुरूप नहीं थी अपीलार्थी को लौटा दी जाएगी और यदि उक्त उपबंधों की अनुपालना के पश्चात् उसके 30 दिन के भीतर पुनः पेश की जाती है तो उसे नहीं रोका जाएगा।

(2) जहां अपील इस नियम के उपनियम (1) के अधीन किन्हीं आधारों पर रोकी गई है वहां अपीलार्थी को उसके लिए तथ्यों और उसके लिए कारणों की सूचना दी जाएगी।

51. **अपील का पारेषण.**—वह प्राधिकारी जिसने वह आदेश किया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है ऐसी अपील की प्राप्ति पर बिना किसी परिहार्य विलंब के और अपील प्राधिकार से किन्हीं निदेशों की प्रतीक्षा किए बिना जब तक अपील नियम 50 के अधीन नहीं रोकी जाती है, अपील प्राधिकार को सुसंगत अभिलेखों के साथ उसे अग्रेषित करेगा।

52. **अपील का विचारण.**—(1) निलंबन के आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में अपील प्राधिकारी यह विचार करेगा कि क्या नियम 31 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते निलंबन का आदेश न्यायोचित है या नहीं और तदनुसार उसे पुष्ट या निरस्त कर देगा।

(2) नियम 34 में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति को अधिरोपित करने वाले या उक्त नियमों के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति को बढ़ाने वाले आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में अपील प्राधिकारी निम्नलिखित विचार करेगा—

(क) क्या इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है या नहीं यदि नहीं तो क्या ऐसी अनुपालना से भारत के संविधान के किन्हीं उपबंधों का अतिक्रमण हुआ है या न्याय नहीं हो पाया है ;

(ख) क्या अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्ष अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर समर्थित है ; और

(ग) क्या अधिरोपित शास्ति या बढ़ाई गई शास्ति अधिक है या पर्याप्त है या अपर्याप्त है और—

(i) शास्ति की पुष्टि करने, बढ़ाने, कम करने या अपास्त करने ; या

(ii) उस प्राधिकारी को, जिसने शास्ति को अधिरोपित किया था या बढ़ाया था या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसे निदेशों के साथ जो मामले की परिस्थितियों में वह ठीक समझे मामले को विप्रेषित करने के आदेश पारित करेगा :

परंतु

(1) यदि ऐसी बढ़ाई गई शास्ति जिसे अपील प्राधिकारी अधिरोपित करना चाहता है, वह नियम 34 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से एक है और मामले में नियम 36 के अधीन पहले से जांच नहीं की गई है तब अपील प्राधिकारी नियम 39 के उपबंधों के अधीन रहते

हुए स्वयं ऐसी जांच करेगा या निदेश देगा कि ऐसी जांच नियम 36 के अनुसार की जाए और उसके पश्चात् ऐसी जांच की कार्यवाहियों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे आदेश करेगा जो वह ठीक समझे, और

(ii) यदि बढ़ाई गई शास्ति जिसे अपील प्राधिकारी अधिरोपित करना चाहता है, वह नियम 34 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से एक है और मामले में नियम 36 के अधीन जांच पहले ही हो गई है तब अपील प्राधिकारी ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे।

53. अपील में के आदेशों का परिपालन—वह प्राधिकारी जिसने वह आदेश किया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों का पालन करवाएगा।

54. पुनरीक्षण—आदेश करने वाले प्राधिकारी से वरिष्ठ कोई प्राधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी जांच के अभिलेखों को मांग सकेगा और इन नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश को पुनरीक्षित कर सकेगा, और—

- (क) और उस आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित या अपास्त कर सकेगा;
- (ख) या उस आदेश द्वारा अधिरोपित शास्तियों को पुष्ट, कम, वृद्धि या अपास्त कर सकेगा या जहां कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है वहां कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ; या
- (ग) उस प्राधिकारी को जिसने आदेश किया था या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसे प्राधिकारी को मामले की परिस्थितियों में जो वह उचित समझे आगे जांच करने के लिए निदेशित करते हुए मामले को विप्रेषित कर सकेगा ; या
- (घ) पुनरीक्षित किए जाने के लिए प्रस्तावित आदेश की संसूचना की तारीख के छः मास के भीतर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ;

परंतु यह कि कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला या वृद्धि करने वाला कोई आदेश किसी पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर संबद्ध सरकारी सेवक को नहीं दिया गया है और जहां नियम 34 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति को अधिरोपित करने की प्रस्थापना की जाती है या उन खंडों में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति को पुनरीक्षित किए जाने के लिए चाहा गया आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को बढ़ाने की प्रस्थापना की जाती है और यदि औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 1969 के नियम 36 के अधीन कोई जांच उस मामले में पूर्व में नहीं कर ली गई है, तब ऐसी कोई शास्ति उपरोक्त नियमों में अधिकथित रीति में जांच के पश्चात् ही अधिरोपित की जाएगी।

(2) अपील से संबंधित नियम 52 के उपबंध जहां तक संभव हो पुनरीक्षण के ऐसे आदेशों को लागू होंगे।

(3) समय-समय पर इस विषय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश और अनुदेश केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1965 के अधीन यथा लागू यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

55. अकार्य दिन—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, अनुशासनिक प्राधिकारी भर्ती किए गए किसी बल सदस्य पर शास्ति अधिरोपित करने के लिए अंतिम आदेशपारित करते समय या अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध संबद्ध भर्ती किए गए किसी बल सदस्य को कारण बताने के लिए अवसर देने के पश्चात् आरोपों उन जिनके परिणामस्वरूप ये शास्तियां अधिरोपित की गई हैं, ऐसे भर्ती किए गए बल-सदस्य को पदच्युत किए जाने, हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति की शास्तियों को अपास्त करने के पश्चात् भर्ती किए गए बल-सदस्य को सेवा में पुनः स्थापित करने पर वह ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह आदेश कर सकेगा कि पदच्युत किए जाने, हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख पुनः स्थापित किए जाने की तारीख के बीच की मध्यवर्ती कालावधि को सेवाओं के प्रयोजनों के लिए अकार्य दिन माना जाएगा।

56. याचिकाएं—(1) भर्ती किया गया कोई बल-सदस्य उसकी शासकीय स्थिति से संबद्ध किसी विषय जिसमें अपील और पुनरीक्षण से संबंधित नियम के अंतर्गत आने वाले विषय से भिन्न उसके व्यक्तिगत हित अन्तर्बलित हैं, की बाबत याचिकाएं पेश कर सकेगा।

(2) प्रत्येक भर्ती किया गया ऐसा बल-सदस्य उसके व्यक्तिगत मामले से संबंधित अकेले ही याचिका पेश करेगा।

(3) किसी भी किस्म की चाहे जो भी मामला हो संयुक्त याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसी याचिकाओं का पेश किया जाना अनुशासन का कार्य माना जाएगा।

(4) ऐसी याचिका उचित प्ररूप में होगी और उसकी शिष्टतापूर्ण होगी और अव्यवहित वरिष्ठ को पेश की जाएगी चाहे याची उस समय छुट्टी पर हो। इस नियम के उल्लंघन में पेश की गई याचिका संक्षिप्त रूप से अस्वीकृत कर दी जाएगी।

(5) ऐसा अव्यवहित वरिष्ठ अपने अव्यवहित वरिष्ठ के माध्यम से उसके निपटान के लिए सक्षम प्राधिकारी को पेश करेगा। उससे वरिष्ठ कोई अधिकारी ऐसी याचिका को रोक सकेगा। यदि वह अधिनीत भाषा में लिखी गई है या अन्यथा अनुचित रूप से लिखी गई है उस मामले में वह याची को लिखित रूप में सूचित करेगा कि उसकी याचिका रोक ली गई है।

(6) सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली पश्चात्पूर्ती याचिका के साथ याची अपनी पूर्ववर्ती याचिका के संबंध में उस आदेश की एक प्रति अपनी याचिका के साथ भी संलग्न करेगा जो उसके अव्यवहित वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसे संसूचित किया गया था।

57. **अन्य उपायों (तरीकों) पर रोक**—पर्यवेक्षक अधिकारियों और भर्ती किए गए बल-सदस्यों को उनके दावों के लिए या कथित शिकायतों को दूर करने के लिए इन नियमों में तरीके से भिन्न किसी विहित प्रक्रिया को अपनाने के लिए निर्णित किया गया है उनकी ओर से ऐसे किसी अन्य तरीके के प्रयास को अनुशासनहीनता का कार्य समझा जाएगा।

अध्याय 12

प्रकीर्ण

58. **त्याग-पत्र**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी परीक्षा की अवधि के दौरान या उसके पश्चात् किसी बल-सदस्य को ऐसी तारीख से जो उसके त्याग पत्र को स्वीकार करने में विनिर्दिष्ट की जाए, उसके पद से पद त्याग करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा :

परंतु यह कि बल में नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की अवधि तक बल के ऐसे सदस्य के त्याग पत्र की स्वीकृति से पूर्व अन्यत्र किसी नौकरी को स्वीकार करने से भिन्न कारण से जिसके लिए कांडर निर्बाधन दिए गए हैं बल में उसको दी गई प्रशिक्षण की लागत को लौटाने की अपेक्षा की जाएगी या तीन मास के वेतन और भत्ते के समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, वापस करने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) बल के किसी ऐसे सदस्य के, जो विचारणाधीन है या जिसका आचरण जांच के अधीन है, पद त्याग करने से इंकार किया जा सकेगा।

59. **सेवानुक्त प्रमाण पत्र**—जब कभी बल-सदस्य किसी भी कारण से ऐसा सदस्य नहीं रह जाता है, इन नियमों के अधीन संलग्न परिशिष्ट "घ" विनिर्दिष्ट प्ररूप में एक सेवानुक्त प्रमाण पत्र उसको दिया जाएगा।

60. **नियुक्ति प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण**—प्रत्येक भर्ती किया गया बल-सदस्य जो बल का सदस्य नहीं रह गया है उसके नियुक्ति प्रमाण पत्र को उसके अव्यवहित वरिष्ठ को अभ्यर्पित करेगा जो उसके पश्चात् कमांडेंट को प्रस्तुत करेगा।

61. **निःशुल्क आवास सुविधा**—(1) सामान्यतः यह परिचयन कि जहां बल को तैनात किया गया है सभी पर्यवेक्षक अधिकारियों और 45 प्रतिशत वैवाहिक और 55 प्रतिशत अवैवाहिक या समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथासंशोधित भर्ती किए गए बल-सदस्यों को स्वयं नगरी में वास सुविधा का उपबंध किया जाएगा।

(2) भर्ती किए गए बल-सदस्यों को आवास सुविधा किराया मुक्त होगी किन्तु जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, वे अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को यथा लागू उसके बदले मकान किराया भत्ता प्राप्त करेंगे।

(3) बल-सदस्यों को इस बाबत समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुबंधनों के अनुसार वैवाहिक आवास सुविधा के बदले प्रतिकर भी प्राप्त करेंगे। प्रतिकर बल के सदस्यों की उस प्रतिशतता के लिए संदेय होगा जो बल के उन सदस्यों को घटाकर जो वैवाहिक आवास सुविधा के प्राप्त करने के हकदार हैं और जिन्हें परिवचन के द्वारा आवास सुविधा आबंटित की जाती है।

(4) बल के पर्यवेक्षक अधिकारी जिसको पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा वास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है या संपदा निदेशालय द्वारा वास सुविधा आबंटित की जाती है उन दरों पर पब्लिक सेक्टर उपक्रमों को अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा जो यथास्थिति उनके अपने कर्मचारियों को लागू होती है या वह अनुज्ञप्ति फीस जो वास सुविधा के कुर्सी क्षेत्र के प्रतिनिर्देश से समय-समय पर साधारण पूल वास सुविधा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाती है।

62. **चिकित्सीय सुविधाएं**—बल के सदस्य केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा के हकदार होंगे और उन स्थानों में जहां ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं वहां वे केन्द्रीय सिविल सेवा (चिकित्सीय परिचारक) नियम, 1944 द्वारा शासित होंगे;

परंतु यह कि जब उन्हें पब्लिक सेक्टर उपक्रम में अभिनियोजित किया जाता है ;

(i) उस दशा में जहां ऐसे पब्लिक सेक्टर उपक्रम अपने कर्मचारियों को चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, ऐसे बल-सदस्य ऐसी सुविधाओं को निःशुल्क प्राप्त करने के हकदार होंगे ; और

(ii) यदि ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तब ऐसे बल-सदस्यों के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (चिकित्सीय परिचारक) नियम, 1944 में यथा उपबंधित प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक की व्यवस्था होगी।

63. **छुट्टी**—पर्यवेक्षक अधिकारी और बल-सदस्य उन छुट्टी नियमों द्वारा शासित होंगे जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू होते हैं इसके अलावा वे फील्ड फारमेशन की बाबत कैलेंडर वर्ष में 15 दिन की आकस्मिक छुट्टी के हकदार होंगे जहां एक दिन में विनिर्दिष्ट कार्यकरण के घंटे या कार्यकरण सप्ताह विहित नहीं है और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बल मुख्यालय, सेक्टर मुख्यालय आदि जैसे स्टेटिक फार्मेशन में आकस्मिक छुट्टी की हकदारी गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 27012/6/98/पी एफ 1/419 तारीख 7-7-2000 के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में आठ दिन की होगी। छुट्टी का नियमितिकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अधीन रहते हुए होगा।

64. छुट्टी से पुनः बुलाना—पर्यवेक्षक अधिकारियों और भर्ती किए गए बल-सदस्य जो छुट्टी पर हैं उनकी छुट्टी मंजूर करने के लिए सशक्त प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय पुनः बुलाया जा सकेगा। ये या तो मुख्यालय पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के लिए या उस स्थान के लिए जिस पर उनकी सेवाएं अपेक्षित हैं सीधे रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किए जा सकेंगे।

प्रत्येक दशा में पुनः बुलाने वाले प्राधिकारी के विवेकाधिकार से उनको दौरे पर जो यात्रा भत्ता मिलता है उसके लिए वापसी यात्रा के लिए (निकटतम मार्ग से) यात्रा भत्ता अनुज्ञात किया जा सकेगा।

65. मुफ्त छुट्टी पास और छुट्टी यात्रा रियायत—(1) मुफ्त छुट्टी पास और छुट्टी यात्रा रियायत हैड कांस्टेबल की रैंक के और उसके नीचे की रैंक के बल-सदस्य के लिए निम्नानुसार अनुज्ञेय होगा, अर्थात्—

- (क) जब उनके कुटुंब से दूर रह रहे हों ड्यूटी के स्थानों से उनके गृह नगरों के निकटतम रेल स्टेशनों तक और वापसी के लिए प्रत्येक वर्ष एक मुफ्त छुट्टी पास जो दो वर्ष की ब्लाक अवधि में उनके कुटुंब के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के अधीन रहते हुए होगा।
- (ख) उस मामले में जहां वे उनके कुटुंब के साथ रह रहे हों और वे उनके कुटुंब के लिए भी छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करना चाहता हो वहां दो वर्ष में एक बार केवल अपने लिए गृह नगर और वापसी के लिए मुफ्त छुट्टी पास और अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को लागू सामान्य छुट्टी यात्रा रियायत नियम के अधीन कुटुंब के सदस्यों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत (दो वर्ष की ब्लाक अवधि में एक बार) के लिए हकदार होंगे।
- (ग) एक मास से अन्यून की अवधि की चिकित्सीय छुट्टी पर जाने पर मुफ्त छुट्टी पास बशर्ते कि यह प्रमाणित किया जाता है कि बीमारी या क्षति जिसके लिए चिकित्सीय छुट्टी की आवश्यकता हुई है बल-सदस्य की ओर से कोई दोष या उपेक्षा से नहीं ली गई है।
- (घ) अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय भारत में किसी स्थान की यात्रा के लिए स्वयं और कुटुंब के सदस्यों के लिए चार वर्ष में एक बार छुट्टी यात्रा रियायत;

परन्तु यह कि खंड (घ) के अधीन अनुज्ञेय छुट्टी यात्रा रियायत खंड (क) के अधीन अनुज्ञेय मुफ्त छुट्टी पास और खंड (ख) के अधीन अनुज्ञेय छुट्टी यात्रा रियायत और मुफ्त छुट्टी पास के बदले में होगा।

(2) पर्यवेक्षक अधिकारी और सहायक उप निरीक्षक तथा उसकी रैंक से ऊपर के बल-सदस्य उसी छुट्टी लिए यात्रा रियायत के पात्र होंगे जिसके लिए इस निमित्त केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसरण में अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी पात्र होते हैं।

66. धनीय इनाम प्रदान करने की शक्ति—धनीय इनाम भर्ती किए गए बल-सदस्यों, अराजपत्रित सरकारी सेवकों, औद्योगिक उपक्रमों के कर्मचारियों और कर्मकारों और नियम 67, 68 और 69 के अनुसार जनता के सदस्यों को प्रदान की जा सकेगी।

67. धनीय इनाम के लिए पात्रता—(1) धनीय इनाम केवल भर्ती किए गए बल-सदस्यों को ही निम्नलिखित के लिए प्रदान की जा सकेगी—

(क) विशेष साहस, कौशल या स्वप्रेरेणा की अपेक्षा वाले उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जैसे—

- (i) अपराधी की गिरफ्तारी ; या
- (ii) अपराध या उससे संबद्ध बातों का पता लगाने की जानकारी को सुनिश्चित करने; या
- (iii) असाधारण अच्छी जांच करने ; या
- (iv) औद्योगिक उपक्रम के संरक्षण, संरक्षा और सुरक्षा के संबंध में अपराधी के साथ मुठभेड़ ;

(ख) कम उत्कृष्ट प्रकृति का कार्यकरण किन्तु जिसमें औद्योगिक उपक्रम के संरक्षण, संरक्षा और सुरक्षा में तात्त्विक सहायता किए जाने के लिए तत्परता, ईमानदारी और बुद्धिमतापूर्ण आदेश के अनुपालन और आज्ञानुपालन अपेक्षित हो ;

(ग) औद्योगिक उपक्रम के संरक्षण, संरक्षा और सुरक्षा के संबंध में अतिरिक्त कठिन कार्य करना ;

(घ) तीव्र बुद्धिमता, निशानेबाजी, परिश्रमशीलता, औद्योगिक उपक्रमों के कर्मचारियों और कर्मकारों या उन व्यक्तियों का जो कारबार के संबंध में औद्योगिक उपक्रमों का दौरा करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए आते हैं उनके सहायक ध्यान रखने के लिए जो आपवादिक मामले में बल की दक्षता में वृद्धि करने के लिए संगणित की जाती है।

(2) प्रत्येक प्राइज के लिए एक हजार से अधिक के मूल्य की पुस्तकों या वस्तुओं के रूप में भी धनीय इनाम प्रशिक्षणार्थियों के प्रत्येक बैच के लिए प्रशिक्षण के दौरान प्रवीणता के लिए भर्ती किए गए बल-सदस्यों को प्रदान की जा सकेंगी जो प्रशिक्षण कालेज या प्रशिक्षण केन्द्र से निकल कर जाते हैं जो नीचे विनिर्दिष्ट अनुसार होंगी—

- I प्राइज—प्रथम रैंक की समग्र दक्षता के लिए ;
- II प्राइज—द्वितीय रैंक की समग्र दक्षता के लिए ;
- III प्राइज—पेरेड, मस्केटरी और स्पोर्ट्स में प्रवीणता के लिए ;

(ii) धनीय इनाम अनुरोध पर प्रदान नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण—संदेह दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी प्रशिक्षणार्थी को जिसके I प्राइज या II प्राइज प्रदान की गई है उसे III प्राइज भी प्रदान करना अनुज्ञेय होगा।

(3) धनीय इनाम अराजपत्रित सरकारी स्लैवकों, औद्योगिक उपक्रमों के कर्मचारियों और कर्मकारों और जनता के सदस्यों को निम्नलिखित में बल की सहायता करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जा सकेगी।

(i) किसी गंभीर मामले का पता लगाने में, या

(ii) किसी अपराधी के पकड़ने में, या

(iii) किसी अपराधी या किसी समाज विरोधी तत्व के प्रतिरोध करने में, या

(iv) किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो औद्योगिक उपक्रमों के बेहतर संरक्षण, संरक्षा और सुरक्षा के लिए हो।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस नियम के प्रयोजनों के लिए—

(i) "साधारण कल्याण कार्य" धनीय इनाम के प्रदान करने के लिए आधार नहीं होगा।

(ii) धनीय इनाम अनुरोध पर प्रदान नहीं किए जाएंगे।

68. धनीय इनाम प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी—(1) पर्यवेक्षक अधिकारी बल की बजट व्यवस्था के अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित नियम 67 के अधीन धनीय इनाम की प्रस्थापना और उन्हें प्रदान करने के लिए सशक्त हैं।

(2) नियम 67 के अधीन धनीय इनाम उसे प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी यदि ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उसकी यह राय है कि वह व्यक्ति इस निमित्त अपेक्षाओं को पूरा करता है।

(3) ऐसे धनीय इनाम प्रदान करने वाला आदेश उसके लिए कारणों और नियम 67 के उपबंध जिनके अधीन यह प्रदान की जाती है, उपदर्शित करेगा।

69. औद्योगिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशक द्वारा प्रस्थापित धनीय इनाम—बल का पर्यवेक्षक अधिकारी नियम 67 के उपनियम (1) से संबंधित माने जा सकने वाले प्रयोजन के लिए किसी औद्योगिक उपक्रम के प्रबंध निदेशक द्वारा प्रस्थापित धनीय इनाम को ग्रहण करने के लिए भर्ती किए गए बल-सदस्यों को अनुज्ञात कर सकेगा।

70. "पद" की जोखिम/ "पद" विशेष जोखिम के कारण होने वाले फायदे—इन मामलों में, पर्यवेक्षक अधिकारी और भर्ती किए गए बल-सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम द्वारा शासित होंगे।

71. अधिवर्षिता आदि—पर्यवेक्षक अधिकारियों और भर्ती किए गए बल-सदस्यों की अधिवर्षिता पेंशन, भविष्य निधि और उपदान से संबंधित नियम वही होंगे जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को लागू होते हैं।

72. स्थानान्तरण—(1) बल-सदस्यों के स्थानान्तरण निम्नानुसार किए जा सकेंगे—

(i) पर्यवेक्षक अधिकारियों के महानिदेशक द्वारा;

(ii) एक कमांडेंट के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक एकक से दूसरे एकक को हैड कांस्टेबल की रैंक तक के, कमांडेंट द्वारा;

(iii) जोन के भीतर एक एकक से दूसरे एकक में भर्ती किए गए बल-सदस्य का उस जोन के उप महानिरीक्षक द्वारा;

(iv) सेक्टर के भीतर एक एकक से दूसरे एकक में भर्ती किए गए बल-सदस्यों का उस सेक्टर के महानिरीक्षक द्वारा;

(v) संपूर्ण बल में एक एकक या जोन से दूसरे में भर्ती किए गए बल-सदस्य का बल मुख्यालय के उप महानिरीक्षक द्वारा।

(2) उपनियम (1) के सक्षम प्राधिकारी से वरिष्ठ प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन किए गए स्थानान्तरण के किसी आदेश को अंतरित, निष्प्रभाव, परिवर्तित या उपांतरित करने का आदेश कर सकेगा।

73. प्रभारों का संदाय—ऐसे उपक्रम में अधिनियम की धारा 14 के अधीन पर्यवेक्षक अधिकारियों और भर्ती किए गए बल-सदस्यों की प्रतिनियुक्ति के लिए पब्लिक सेक्टर में औद्योगिक उपक्रम द्वारा संदेय प्रभार को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, संदत्त किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इन नियम के प्रयोजनों के लिए पब्लिक सेक्टर में किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा संदेय प्रभारों के अंतर्गत निम्नलिखित होगा—

(i) उस उपक्रम में तैनात अधिकारियों और भर्ती किए गए बल-सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते, छुट्टी वेतन अभिदाय और पेंशन अभिदाय;

(ii) वस्त्रों की लागत, उपस्कर परिवहन, आयुध और गोला-बारूद और ऐसे अधिकारियों और सदस्यों के कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए अन्य आवश्यक साज सज्जा; और

(iii) ऐसी राशि जो केन्द्रीय सरकार औद्योगिक उपक्रम में तैनात अधिकारियों, बल-सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखते हुए और बल के मुख्यालय और अन्य स्थापनों के अनुरक्षण की लागत के संबंध में औद्योगिक उपक्रम द्वारा संदेय की जाने वाली आनुपातिक राशि जो समय-समय पर अवधारित की जाए।

74. कठिपय मामलों में नियमों का लागू न किया जाना—(1) ये नियम संविदा पर लिए गए भर्ती किये गये बल-सदस्यों को लागू नहीं होंगे, जो उनकी संविदा की शर्तों द्वारा शासित होंगे।

(2) इन नियमों की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वे निम्नलिखित से राष्ट्रपति को रोकते हैं—

(क) बल में ऐसी किसी नियुक्ति करने से जो वह आवश्यक समझे; या

(ख) कोई आदेश पारित करने से या किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन पारित किसी आदेश के स्वप्रेरणा से या अन्यथा पुनरीक्षित करने से।

75. महानिदेशक की कमेंडेशन डिस्क की अवार्ड—(1) महानिदेशक की कमेंडेशन डिस्क केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक को निम्नलिखित आधार पर प्रदान की जाएगी :

(क) कार्य के दौरान सहज दृश्य उपलब्धि के लिए।

(ख) प्राकृतिक आपदाओं में प्रशंसनीय कार्य।

(ग) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए खेल-कूद में उत्कृष्ट उपलब्धि।

(घ) कोई नयी खोज जो बल के कार्यकरण में महत्वपूर्ण सुधार ला सके।

(ङ) 15 वर्ष तक की सेवा के स्वच्छ और अच्छे अभिलेख।

(च) 20 वर्ष की लगातार अवधि तक दुर्घटनामुक्त वाहन चालन और अच्छे अभिलेख।

(छ) 12 सप्ताह के दौरान और उससे अधिक के सैन्य पाठ्यक्रम में "ए एक्स" ग्रेड दिए जाने के लिए।

(ज) कठिन मामलों में प्रक्रिया में किन्हीं सहज दृश्य प्रयासों के लिए।

(झ) सहज दृश्य के लिए जो प्रशंसनीय प्रकृति का समझा जाए।

(ञ) कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के मामले में 20,000/- रुपये से अधिक और सहायक उपनिरीक्षक से निरीक्षकों के मामले में 50,000/- रुपये से अधिक और राजपत्रित अधिकारियों के मामले में 1,00,000/- रुपये से अधिक मूल्य की सम्पत्ति की वसूली। ऐसी वसूली की गई सम्पत्ति अदावाकृत प्रकृति की होनी चाहिए।

(ट) आतंकवादियों/अपराधियों के साथ निपटने में उत्कृष्ट कार्यवाई जिसके लिए शौर्य पदक की अवार्ड की अपेक्षा नहीं की जाती है।

(ठ) बल स्तर पर वृत्तिक पाठ्यक्रमों में प्रथम आना या अंतरबल स्तर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करना।

(ड) कार्मिक जो किसी उत्कृष्ट कार्य के कारण बिना बारी के प्रोन्नत कर दिए गए हैं उन पर भी विचार किया जा सकता है।

(2) इस विषय पर विस्तृत अनुदेश केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर पृथक रूप से जारी किए जाएंगे।

76. अनुसचिवीय कर्मचारिचूद—अनुसचिवीय कर्मचारिचूद (सिविलियन) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गए भर्ती नियमों द्वारा शासित होंगे।

77. सेवा की अन्य शर्तें—बल के सदस्य सेवा की शर्तों के संबंध में सभी विषयों की बाबत जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं है या अपर्याप्त उपबंध किए गए हैं, ऐसे विषयों की बाबत केन्द्रीय सरकार में तत्समान पद धारण करने वाले अधिकारियों को तत्समय लागू नियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

अध्याय 13

भर्ती किए गए बल-सदस्य द्वारा किए गए किसी अपराध और इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों की जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति

78. मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ—अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराधों की जांच करने और विचारण के प्रयोजन के लिए और ऐसे अपराधों की ऐसी जांच करने या विचारण से आनुवंशिक सभी विषयों की बाबत नियम 4 के उपनियम (1) के खंड (क) के उपखंड (iv) में यथावर्णित कमांडेंट या उसके समतुल्य रैंक धारण करने वाला प्रत्येक अधिकारी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

79. न्यायिक विचारण—अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में संभो विचारण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंधों के अनुसार किए जाएंगे।

80. मजिस्ट्रेट—इस अध्याय के प्रयोजन के लिए "मजिस्ट्रेट" से ऐसा कमांडेंट अभिप्रेत है जिसको अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2)(क) के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

81. कमांडेंट के समक्ष कार्यवाहियों में प्रयोग की जाने वाली भाषा—अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध की जांच करने या विचारण करने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय कमांडेंट द्वारा या तो अंग्रेजी या हिंदी का प्रयोग किया जा सकेगा।

82. मजिस्ट्रेट द्वारा भर्ती किए गए बल-सदस्यों का विचारण न किया जाना—जहां भर्ती किया गया बल-सदस्य मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है और अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध से आरोपित किया जाता है जिसके लिए वह विचारण किए जाने का दायी है वहां ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध की जांच या विचारण की कार्यवाही तब तक नहीं करेगा जब तक कि—

- (क) ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उसकी यह राय है कि उसे एकक कमांडेंट द्वारा उसके पास भेजे जाने बिना इस प्रकार कार्यवाही नहीं करनी चाहिए; या
- (ख) एकक कमांडेंट द्वारा उसके पास नहीं भेजा जाता है।

83. मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना का दिया जाना—नियम 82 के खंड (क) के अधीन कार्यवाही से पूर्व मजिस्ट्रेट एकक कमांडेंट को लिखित सूचना देगा और ऐसी सूचना की तारीख से 21 दिन की अवधि की समाप्ति तक वह :

- (क) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 252, धारा 255(1) और (2) धारा 256 या धारा 257 के अधीन अभियुक्त को दोषसिद्ध या दोषमुक्त नहीं करेगा या उक्त संहिता की धारा 254 के अधीन प्रतिरक्षा में उसको नहीं सुनेगा; या
- (ख) उक्त संहिता की धारा 238 या धारा 246 (1) के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध किसी आरोप की लिखित रूप में विरचना नहीं करेगा; या
- (ग) उक्त संहिता की धारा 193 के अधीन सेशन न्यायालय द्वारा विचारण के लिए अभियुक्त को सुपुर्द करने का कोई आदेश नहीं करेगा; या
- (घ) उक्त संहिता की धारा 192 के अधीन जांच या विचार के लिए मामले को अंतरित नहीं करेगा।

84. अभियुक्त के विचारण के संबंध में मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाना—(1) जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा भेज दिया गया हो तब एकक कमांडर मजिस्ट्रेट को यथाशीघ्र सूचित करेगा कि क्या अभियुक्त का उसके द्वारा विचारण किया जा चुका है या अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए आदेशित कोई अन्य शासकीय कार्यवाही की जा चुकी है या नहीं।

(2) जब मजिस्ट्रेट को उपनियम (1) के अधीन सूचना दे दी गई है कि अभियुक्त पर विचारण नहीं किया गया है या कोई शासकीय कार्यवाही नहीं की गई है अथवा उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए आदेशित किया गया है तब मजिस्ट्रेट केन्द्रीय सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध विधि के अनुसार संव्यवहार किया गया है समुचित कदम उठाने के लिए परिस्थितियों की रिपोर्ट करेगा।

85. कमांडर द्वारा अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना—जहां भर्ती किए गए किसी बल-सदस्य ने ऐसा अपराध किया है जिसका एकक कमांडर की राय में बल में विधि के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जाना है वहां एकक कमांडर संबंध मजिस्ट्रेट को लिखित सूचना देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को उचित अनुरक्षक के अधीन मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।

86. कारावास की रीति—अधिनियम के अधीन कारावास से दंडादिष्ट भर्ती किए गए किसी बल-सदस्य को निकटतम कारागार में परिरुद्ध किया जाएगा :

परंतु यह कि यदि कारावास एक मास या उससे कम के लिए है या जहां एकक कमांडर का यह समाधान हो जाता है कि निकटतम कारागार के लिए कारावास से दंडित भर्ती किए गए बल-सदस्य के परिवहन और अनुरक्षक की कठिनाई के कारण ऐसा वांछनीय हो जाता है तब ऐसे व्यक्ति को बल के क्वार्टर गार्ड में परिरुद्ध किया जाएगा।

87. बल अभिरक्षा—(1) जहां एकक कमांडर की यह राय है कि भर्ती किए गए किसी बल-सदस्य ने कोई अपराध किया है और उसका विचारण ऐसे कमांडेंट द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें धारा 18(2क) के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित हैं वहां ऐसे कमांडेंट के लिए उप महानिरीक्षक के पूर्व अनुमोदन से भर्ती किए गए बल-सदस्य को बल की अभिरक्षा में लिए जाने और या तो बंद, गिरफ्तारी में या खुली गिरफ्तारी में रखे जाने के लिए, आरोप की गंभीरता और उपस्थित परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए समय-समय पर जैसा वह ठीक समझे आदेश करना न्यायपूर्ण होगा :

परंतु यह है कि कोई भर्ती किया गया बल-सदस्य कमांडेंट/मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण संयोजित किए जाने बिना या अधिनियम की धारा 8 के अधीन उसे दंड किए जाने बिना 8 दिन से अधिक की अवधि के लिए बल की अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा;

(2) प्रत्येक एकक या समूह में उप निरीक्षक द्वारा जैसा आवश्यक समझा जाए एक या अधिक परिरोध के स्थान होंगे जहां गिरफ्तार किए गए भर्ती किए गए बल-सदस्य को निरुद्ध किया जाएगा ऐसे स्थान एकक के कमांडेंट, उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट के पर्यवेक्षण के अधीन होंगे जो उनके अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे।

(3) यदि कोई भर्ती किया गया बल-सदस्य बल की अभिरक्षा से निकलकर भागता है या छुड़ा लिया जाता है तब वह बल-सदस्य जिसकी अभिरक्षा से वह निकल कर भागा था या छुड़ाया गया था निकलकर भागने या छुड़ाए जाने की रिपोर्ट पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को करेगा और तुरंत ऐसे भर्ती किए गए बल-सदस्य का भारत में किसी स्थान में पीछा कर सकेगा और गिरफ्तार कर सकेगा।

88. दंडादेश की प्रख्यापना—मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए दंडादेश को उसके सुनाए जाने के पश्चात् सर्वप्रथम अवसर पर प्रख्यापित किया जाएगा और अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रख्यापना के पश्चात् बिना विलंब के कार्यान्वित किया जाएगा।

89. कार्यवाहियों का पारेषण—(1) प्रत्येक मजिस्ट्रेट की कार्यवाही उप महानिरीक्षक को उसकी सूचना के लिए बिना विलंब अग्रेषित की जाएगी जिसकी कमान के भीतर विचारण किया गया था।

90. अपील—इस अध्याय के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण पर सिद्ध दोष ठहराया गया कोई व्यक्ति सेशन न्यायालय को अपील कर सकेगा। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के वे उपबंध जो उस संहिता में अपील से संबंधित हैं इस नियम के अधीन अपीलों को लागू होंगे।

अध्याय 14

91. प्राइवेट सेक्टर में औद्योगिक स्थापनों को तकनीकी परामर्शी सेवाएं—(क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय/राज्य सरकारी विभागों, पब्लिक, संयुक्त, प्राइवेट सेक्टर, स्वायत्त निकायों में औद्योगिक स्थापनों को या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संस्था को तकनीकी परामर्शी सेवाएं प्रदान कर सकेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएं होंगी :

- (i) औद्योगिक सुरक्षा और अग्नि परित्राण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना और उचित हल का सुझाव देना।
- (ii) प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से, जो केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रशिक्षण संस्थाओं पर या मुचकिल के औद्योगिक स्थापनों या किसी अन्य स्थान जो महानिदेशक द्वारा ठीक समझा जाए, पर संचालित किए जा सकेंगे, परामर्श लेने वाले (जिसे इसमें इसके पश्चात् मुचकिल कहा गया है) या उसके कर्मचारियों को औद्योगिक सुरक्षा और अग्नि परित्राण के क्षेत्र में ज्ञान और कौशल प्रदान करना।
- (iii) औद्योगिक संरक्षा, सुरक्षा और अग्नि परित्राण के क्षेत्रों में प्रशिक्षण और प्रमाणन पाठ्यक्रमों को संचालित करना और उसके लिए विहित फीस प्रभारित करना। ऐसे विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस महानिदेशक द्वारा अवधारित की जाएगी।
- (iv) मुचकिल के लिए औद्योगिक और अग्नि परित्राण स्क्रीमों के उपायों, नियंत्रणों और प्रणाली की योजना तैयार करने, डिजाइन करने और प्रभावशील करना।
- (v) सुझाए गए उपायों, नियंत्रणों और प्रणालियों के कार्यकरण की मानिटरी के पश्चात् फीड बैक की व्यवस्था करना।
- (vi) संसूचना नेटवर्क की योजना तैयार करना और उसकी डिजाइन करना और संबंधित प्रचालन अनुदेशों को विरचित करना।
- (vii) औद्योगिक सुरक्षा और अग्नि परित्राण से संबंधित अनुदेशों, मानक आदेशों और मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का प्रारूप तैयार करना।
- (viii) आपदा प्रबंध और आकस्मिक योजना तैयार करना और ऐसी योजनाओं के पूर्व अभ्यासों का पर्यवेक्षण या संचालन।
- (ix) औद्योगिक सुरक्षा, औद्योगिक संरक्षा या अग्नि संरक्षा के क्षेत्र में लेखा परीक्षा करना।
- (x) औद्योगिक सुरक्षा, औद्योगिक संरक्षा और अग्नि परित्राण के क्षेत्र में और उनसे संबंधित विषयों में स्वतंत्र रूप से या मुचकिलों और/या अन्य प्रतिष्ठित अभिकरणों के सहयोग से अनुसंधान और सुधार क्रियाकलापों को आरंभ करना।

(ख) प्राइवेट सेक्टर में किसी औद्योगिक स्थापन के प्रबंध निदेशक से या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से अनुरोध की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किन्हीं साधारण निदेशनों के अधीन रहते हुए अनुरोध की जांच के पश्चात् महानिदेशक यदि यह उचित समझता है तो प्रबंध निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को तकनीकी परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के निबंधनों और शर्तों को अग्रेषित कर सकेगा और तकनीकी परामर्शी सेवाओं के लिए विहित फीस भेजने के लिए कह सकेगा।

(ग) प्राइवेट सेक्टर में किसी औद्योगिक स्थापन के प्रबंध निदेशक से विहित फीस भेजे जाने पर महानिदेशक बल के किसी अधिकारी को नाम निर्देशित कर सकेगा या नियम 91 (क) के उपनियम (i) से (x) में वर्णित किसी विषय से संबंधित संबद्ध औद्योगिक स्थापन की तकनीकी अध्ययन करने के लिए अधिकारियों के एक दल का गठन कर सकेगा।

(घ) महानिदेशक यदि यह उचित समझता है और यदि चाही गई परामर्शी की प्रकृति ऐसी अपेक्षा करती है तो उस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले किसी व्यक्ति को भी उपनियम (ग) के अधीन गठित दल के साथ सहयोजित कर सकेगा जिसकी विशेषज्ञता बल के सदस्यों के साथ उपलब्ध नहीं है।

(ङ) नियम (ब) के उपबंधों के अधीन दल के साथ सहयोजित विशेषज्ञ व्यक्ति को उसकी विशेषज्ञता, कालावधि के अनुसार योगदान, सेवाओं और निश्चित परिस्थितियों में ऐसे विशेषज्ञों की उपलब्धता की स्थिति पर विचार करके ऐसी राशि संदत्त की जाएगी जो उचित समझी जाए।

(च) उपधारा (ग) के अधीन महानिदेशक द्वारा इस प्रकार नाम निर्दिष्ट अधिकारी या इस प्रकार गठित बल ऐसे अध्ययन करने के पश्चात् जो वह उचित समझे एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे महानिदेशक को भेजेगा। बल के महानिदेशक के सम्यक अनुमोदन के पश्चात् इस प्रकार तैयार की गई परामर्शी रिपोर्ट प्राइवेट सेक्टर में संबद्ध स्थापन के प्रबंध निदेशक को या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को संसूचित की जाएगी।

(छ) मुवकिकल स्थापन के लिए इस प्रकार तैयार की गई परामर्शी रिपोर्ट स्थापन की संपत्ति होगी और ऐसी रिपोर्ट बल के किसी सदस्य द्वारा या परामर्शी बोर्ड के साथ सहयोजित ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्तिगत फायदे के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएगी। तथापि ऐसी रिपोर्ट शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा सकती है।

(ज) परामर्शी फीस—परामर्शी फीस प्राइवेट सेक्टर में औद्योगिक स्थापनों से समय-समय पर यथा विहित प्रभारित की जाएगी।

92. निरसन और व्यावृत्ति—(1) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 1969 निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त नियमों के अधीन ऐसी कोई बात या ऐसी कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

परिशिष्ट "क"

(नियम 21 देखिए)

करार का प्रारूप

सेवा में,
भारत के राष्ट्रपति

राष्ट्रपति द्वारा मुझे केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पद* पर नियुक्त किए जाने के सहमत होने के फलस्वरूप,

- निरीक्षक
- उपनिरीक्षक
- सहायक उपनिरीक्षक
- हेड कांस्टेबल
- कांस्टेबल

मैं पुत्र निम्नलिखित के लिए सहमत हूँ

और वचन देता हूँ कि :—

- (i) बल में मेरी नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सेवा करूंगा;
- (ii) पंक्ति में मेरे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुझे सौंपे गए सभी कर्तव्यों का पालन और सभी विधिपूर्ण आदेशों का पालन करूंगा;
- (iii) मेरी आरंभिक प्रशिक्षण की अवधि के दौरान अथवा उसके पश्चात् केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कार्य ग्रहण करने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के दौरान बल से अन्यत्र ऐसे कार्य को स्वीकार करने से भिन्न कारण से, जिसके लिए संवर्ग द्वारा स्वीकृति दे दी गई है, बल से अपना त्यागपत्र दिए जाने की दशा में बल में प्रदान किए गए प्रशिक्षण की संपूर्ण लागत अथवा तीन मास के वेतन और भत्ते के समतुल्य रकम का, इसमें से जो भी अधिक हो, प्रतिसंदाय करूंगा; और
- (iv) यदि दस वर्ष के पश्चात् मैं त्यागपत्र देने की वांछा करता हूँ तो मैं इस संबंध में लिखित में आवेदन प्रस्तुत करूंगा और मैं तब तक अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझे सम्यक् रूप से कार्यभार मुक्त नहीं कर दिया जाता।

टिप्पण : स्तंभ (iii) में प्रयुक्त वेतन और भत्ते पद से उसके द्वारा अपने त्याग पत्र दिए जाने की तारीख से ठीक पूर्व तीन मास की अवधि के दौरान प्राप्त किए गए प्रायिक वेतन और भत्ते अभिप्रेत हैं।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

साक्षी

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

तारीख.....

स्थान.....

कर्मचारी के हस्ताक्षर

पदनाम.....

तारीख.....

स्थान.....

स्वीकृत

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

परिशिष्ट "ख"

(नियम 30 देखिए)

"मैं"..... सत्यनिष्ठ से प्रतिज्ञान करता

हूँ कि मैं भारत के प्रति और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा।

हस्ताक्षर.....

पर्यवेक्षकीय अधिकारी के हस्ताक्षर

और पदनाम (जिसकी उपस्थिति में

प्रतिज्ञान किया गया)

परिशिष्ट "ग"

(नियम 17 देखिए)

(चिकित्सीय परीक्षा रिपोर्ट)

(केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के समूह 'ग' और समूह 'घ' कार्मिकों के लिए)

भर्ती बोर्ड के
अध्यक्ष द्वारा
अनुप्रमाणित
अभ्यर्थी का फोटो

भाग-1

प्ररूप का तब प्रयोग किया जाना है जब किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर आरोग्यता के लिए चिकित्सा परीक्षा के लिए स्वयं उपस्थित होने के लिए प्राधिकार दिया गया हो।

नाम.....

.....जाती या मूलवंश.....

.....निवास.....

.....पिता का नाम और

निवास सन् ईस्वी में यथाशक्य निकटतम अभिनिश्चित

अभिनिश्चित जन्म की तारीख :

माप द्वारा वास्तविक ऊँचाई :

ऊँचाई

सीना

वजन

व्यष्टिक के हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

नियुक्ति अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम.....

भाग-2

अभ्यर्थी का कथन और घोषणा

अभ्यर्थी को अपनी चिकित्सीय परीक्षा से पूर्व नीचे अपेक्षित कथन करना चाहिए और इससे उपाबद्ध घोषणा पर हस्ताक्षर करने चाहिए। उसका ध्यान विशिष्टतया नीचे टिप्पण में अंतर्विष्ट चेतावनी की ओर निर्दिष्ट किया जाता है :—

1. (क) क्या कभी आपको चेचक, आन्तरायिक, या कोई अन्य ज्वर ग्रंथियों का विस्तारण या पूयता, हृदय रोग के रूप में खून थूकना, मूर्छा, या संसक्त आमवात हुआ था ?

(ख) कोई अन्य ऐसी बीमारी या दुर्घटना जिसमें विस्तर तक परिरुद्ध रहना और दीर्घकालिक चिकित्सीय या शल्य चिकित्सीय उपचार अपेक्षित हो।

2. आपको अंतिम बार टीका कब लगा ?

3. क्या आप या आपका कोई अन्य नातेदार यक्ष्मा, सैरोफ्यूलस, गाउट दमा, दौरा, मिरगी अथवा पागलपन से पीड़ित रहे हैं ?

4. क्या आप अत्यधिक कार्य या किसी अन्य कारण से किसी भी प्रकार की अधीरता से ग्रस्त रहे हैं ?

5. क्या आपकी गत तीन वर्ष के भीतर चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा बोर्ड द्वारा सरकारी सेवा के लिए परीक्षा की गई है और उसमें अनुपयुक्त घोषित किए गए हैं।

मैं घोषणा करता हूँ कि उपयुक्त सभी उत्तर मेरे सर्वोत्तम विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। मैं सत्यनिष्ठा से यह भी प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैंने किसी बीमारी या अन्य परिस्थितियों के कारण निःशक्तता/प्रमाणपत्र/पेंशन प्राप्त नहीं की है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए

टिप्पण :—अभ्यर्थी उपर्युक्त कथन की परिशुद्धता के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा, जानबूझकर किसी जानकारी छिपाए जाने की दशा में वह यह जोखिम उठाएगा कि नियुक्ति समाप्त हो जाएगी और यदि नियुक्ति हो गई है तो उसके सभी अधिवार्षिकी भत्ते या उपदान संप्रहृत हो जाएंगे।

भाग-3

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने पुत्र की, जो केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में नियोजन के लिए एक अभ्यर्थी है परीक्षा कर ली है और मैं नहीं पाता हूँ कि उसे अंतर्वर्क, सपाट पैर और को अपवर्जित करके कोई रोग, शारीरिक रचना संबंधी पीड़ा या शारीरिक विकृति हो।

मैं/हम, इसे केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में नियोजन के लिए कोई निरर्हता समझता हूँ/समझते हैं, उसके स्वयं के कथनानुसार उसकी आयु है।

इसे अंतर्वर्क सपाट पैर, धनर्जबी, तिर्यक दृष्टि, बाईं आंख बंद करने में असमर्थता, अंगुलियां समुचित रूप से घुमाने में असमर्थता, अपस्फीत सिरा या किसी अन्य स्पष्ट निःशक्तता, जिससे केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के किसी सदस्य के रूप में कार्याकरण को प्रभावित होने की संभावना हो के लिए अभ्यर्थी की परीक्षा करने के पश्चात् भरा जाए।

1. साधारण विकास	अच्छा	स्वच्छ	खराब
2. शारीरिक गठन	पतला	औसत	स्थूल
3. आंखें	दांयी	बाईं	

(क) कोई स्पष्ट रोग

(i) बाह्य

(ii) माध्यक

(ख) दृष्टि तीक्ष्णता

(i) दूर की

(ii) निकट की

(ग) रंग दृष्टि

4. कान, नाक और गला दाईं बाईं

(क) कोई स्पष्ट रोग

(ख) श्रवण

(ग) रंग दृष्टि

5. दांतों की दशा दातुर बिन्दु

6. श्वसन प्रणाली :

(i) छाती का प्रकटन

(ii) श्वास दर

(iii) स्टेथेस्कोपिक परीक्षण के पर कोई असामान्यता

7. (क) परिसंचारी प्रणाली

हृदय : कोई अवयव विक्षति

दर : खड़े होने पर

25 बार स्पंदन के पश्चात्

स्पंदन के 2 मिनट के पश्चात्

(ख) रक्त दाब

प्रकुंचन

अप्रकुंचन

8. उदर :

(क) कोमलता

(ख) स्पर्श ग्राह्यता

(i) यकृत :

(ii) तिल्ली :

(iii) गुर्दा :

(ग) हेक्मोराईड्स

(घ) विदर/नालवृण

(ङ) हार्निलया/हाइड्रोसील

(च) कोई अन्य :

9. गतिविषयक प्रणाली :

(i) रीढ़ की दशा

(ii) अंग के जोड़ों की दशा

10. स्नायु प्रणाली :

(i) स्नायु अस्थिरता का साक्ष्य :

(ii) कंपन :

(iii) मानसिक रोग का पूर्ववृत्त :

11. छाती की विकिरण परीक्षा यदि की गई है, की रिपोर्ट :

12. क्या अभ्यर्थी के स्वास्थ्य की कोई ऐसी बात है जो उसे सेवा में जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में अनुपयुक्त बनाने की संभावना हो ?

13. उस सेवा का उल्लेख करें जिसके लिए अभ्यर्थी की परीक्षा की गई है (जीडी/अनुसर/ट्रेड/संचार/चिकित्सा आदि)
14. चेकक, टीकाकरण चिह्न (संख्या और स्थान भरें)
15. वे मामूली दोष जो ध्यान में लिए गए हैं, जो निरर्थक किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
16. अभ्यर्थी को अनुपयुक्त करने के लिए कारण बताएं।
17. अनुपयुक्त/अस्थायी अनुपयुक्त/उपयुक्त

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

तारीख सहित चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर

1.

2.

परिशिष्ट-‘ब’

सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र

(केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 2000 के नियम 59 के अधीन)

विशिष्टियां

1. नाम
2. पिता का नाम
3. धर्म
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति है
5. जन्म की तारीख
6. पहचान चिह्न, यदि कोई हो
7. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की वह शाखा जिसमें वह अभिनियोजित है (कार्यपालक/अग्निशमन/अनुसन्धिवीय)
8. से तक सेवा की अवधि
9. नियुक्ति प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख [1983 और 1989 के अधिनियम द्वारा यथा उपांतरित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 6(1) देखिए]
10. उपर्युक्त मद संख्या 9 में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र के प्रत्याहरण की तारीख [1983 और 1989 के अधिनियम द्वारा यथा संशोधित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 6(2) देखिए]
11. सेवा में सदस्य न रहने से ठीक पूर्व धारित पद
12. सेवा में सदस्य न रहने से पूर्व वेतन
13. सेवोन्मुक्ति के कारण
14. प्रदान किए गए पदक/अलंकरण
15. चरित्र
16. कर्मचारी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

स्थान :

पर्यवेक्षकीय अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

तारीख :

सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र में "चरित्र" के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाया जाएगा :—

क्रम सं.	मूल्यांकन का प्रवर्ग	शर्तें
1.	उदाहरणात्मक	(i) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा। (ii) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम या सिविल/दांडिक न्यायालय के अधीन कोई दंड कितनी बार दिया गया। (iii) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की क्वालिटी।
2.	बहुत अच्छा	(i) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में न्यूनतम 7 वर्ष की सेवा। (ii) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 8(i) और 18 के अधीन या सिविल/दांडिक न्यायालय के अधीन कोई दंड कितनी बार दिया गया। (iii) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की क्वालिटी।
3.	अच्छा	(i) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधीन किसी मुख्य या लघु दंड रहित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कम से कम 3 वर्ष की सेवा। (ii) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए रैंक या श्रेणी में कोई अवनति कितनी बार की गई। (iii) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की क्वालिटी।
4.	अच्छा	(i) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम और नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए रैंक या श्रेणी में अवनति एक से अधिक बार नहीं की गई हो।
5.	खराब	(i) ऐसे मामले जो उपर्युक्त जो मद सं. 1 से 4 तक में नहीं आते हैं। (ii) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम और नियमों के अधीन दो से अधिक बार रैंक या श्रेणी में अवनति।

अनुसूची-1

विषय-32 देखें

अनुशासनिक प्राधिकारियों और बल के सदस्यों के विभिन्न वर्गों, श्रेणियों और रैंकों की बाबत पारित करने की उनकी शक्तियों की अनुसूची

अनुशासनिक प्राधिकारी और उनकी शक्ति का विस्तार

क्रम सं.	अनुशासनिक आदेश की प्रकृति	महानिदेशक	सेक्टर महानिरीक्षक/महानिरीक्षक (मुख्यालय)	उपमहानिरीक्षक	कमांडेंट	डिप्टी कमांडेंट	सहायक कमांडेंट
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	निलंबन	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य
2.	पदच्युति	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	निरीक्षक के अतिरिक्त बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	—	—
3.	पद से हटाया जाना	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	निरीक्षक के अतिरिक्त बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	—	—
4.	अनिवार्य सेवानिवृत्ति	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	निरीक्षक के अतिरिक्त बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
5. वेतन श्रेणी या रैंक की अवनति	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	निरीक्षक के अतिरिक्त बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	—	—	—
6. संघर्षी प्रभाव के बिना और उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति करना।	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य
7. प्रोन्नति रोकना	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य
8. वेतनवृद्धि रोकना	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य
9. किसी विशिष्ट पद से हटाना या विशेष परिलब्धियों से वंचित करना।	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य
10. सात दिन से अधिक के वेतन के बराबर रकम का जुर्माना	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य
11. परिभिन्दा करना	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य	बल के सभी भर्ती किए गए सदस्य
12. दंड, ड्रिल, एक्स्ट्रागार्ड, हेड कान्टेबल/फटीक या अन्य	कान्टेबल/अनुचर	कान्टेबल/अनुचर	कान्टेबल/अनुचर	कान्टेबल/अनुचर	कान्टेबल/अनुचर	कान्टेबल/अनुचर	कान्टेबल/अनुचर

[सं. ई-32012/2/84-विधि च नियमन/कार्मिक-1]

ओ.पी. आर्य, संपुक्त सचिव (पुलिस)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2001

G.S.R. 825(E).—In exercise of the powers conferred by section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement**—(1) These rules may be called the Central Industrial Security Force Rules, 2001.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions**—In these rules, unless the context otherwise requires—
 - (a) “Act” means the Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968);
 - (b) “Appendix” means an appendix to these rules;
 - (c) “Close arrest” means confinement of any enrolled member of the Force within the Force or a detachment of the Force or a post quarter guard, building or tent under charge of a guard;
 - (d) “Magistrate” means any Magistrate as referred to in section 3 of the Code of Criminal Procedure, 1973;
 - (e) “Open arrest” means confinement of any enrolled member of the Force within the precinct of any barrack, lines or camp for the time being occupied by any detachment of the Force;

- (f) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
- (g) "Section" means a section of the Act;
- (h) The expressions "Assault", "Criminal Force", "Reason to believe", "Wrongfully restrain" and "voluntarily causes hurt" have the meaning assigned to them respectively in Indian Penal Code;
- (i) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

COMPOSITION OF THE FORCE

3. Constitution of the Force—(1) The Force shall consist of the following three branches, namely :—

- (i) Executive Branch;
- (ii) Fire Service Branch; and
- (iii) Ministerial Branch

(2) Each Branch shall consist of such supervisory officers (other than the Director General) and enrolled members of the Force as the Director General may from time to time specify.

4. Composition of the Force—The Supervisory Officers and enrolled members of the Force shall be classified in accordance with the ranks in the following categories, namely :—

(1) (a) Supervisory Officers

- (i) Director General;
- (ii) Inspector General;
- (iii) Deputy Inspector General, Deputy Inspector General (Fire) and Director, National Industrial Security Academy;
- (iv) Commandant, Assistant Inspector General, Assistant Inspector General (Fire), Commandant (Fire), Group Commandant, Principal, Recruits Training Centre, Principal, Fire Service Training Institute, Assistant Director, National Industrial Security Academy.
- (v) Deputy Commandant and Deputy Commandant (Fire) and Joint Assistant Director, National Industrial Security Academy.
- (vi) Assistant Commandant, Vice Principal, Recruits Training Centre, Assistant Commandant (Junior Administrative Officer) and Assistant Commandant (Fire) and Deputy Assistant Director, National Industrial Security Academy.

(b) Enrolled Members

- (vii) Inspector (Executive, Stenographer, Ministerial, Fire and Armourer)
- (viii) Sub-Inspector (Executive, Stenographer, Ministerial, Fire and Armourer);
- (ix) Assistant Sub-Inspector (Executive, Ministerial, Fire and Armourer);
- (x) Head Constable (Driver, Executive, Fire and Armourer);
- (xi) Constables (Executive, Fire, Armourer); and
- (xii) Followers (Cook, Kahar, Sweeper, Mochi, Barber, Carpenter, Tailor, Dhobi, Charge Mechanic, Motor Pump Attendant, Switch Board Attendant and Painter). Each of the above categories of ranks other than the ranks mentioned at item No. (xii) shall be the immediate superior in rank to the rank mentioned below that category.

(2) Unless the context otherwise requires, reference to Commandant, Deputy Commandant, Assistant Commandant, Inspector, Sub-Inspector, Assistant Sub-Inspector, Head Constable, Constable and Followers in these rules shall be deemed respectively to include references to all or any of the ranks of Supervisory Officers or enrolled members of the Force as the case may be specified in items (iv) to (xii) of sub-rule (1).

5. Conferment of local rank—Notwithstanding anything contained in these rules, the Director General may, subject to confirmation of the Central Government, grant to an officer of the Force a higher rank than held by him, as a local rank, whenever considered necessary by him in the interest of better functioning of the Force—

- (i) a local rank shall be conferred by the Director General up to and including the rank of Commandant only.
- (ii) local rank to the officers of the level of Deputy Inspector General and above shall be conferred after prior approval of the Ministry of Home Affairs.

(iii) the power of conferring local ranks will not be further delegated by the Director General to any of the officers subordinate to him.

(iv) an officer of the Force who has been granted a local rank—

(a) shall exercise the command and be vested with the powers of an officer holding that rank;

(b) shall cease to hold that rank, if the grant of such rank is not confirmed within 21 days by the Central Government, or when so ordered by the Director General or when he ceases to hold the appointment for which the rank is granted,

(c) shall not be entitled to any extra pay and allowances for holding such rank,

(d) shall not be entitled to claim any seniority over other officers of the Force by virtue of having held such rank.

6. Duties of Director General—(1) The Director General shall be the Head of the Force and shall be responsible for maintaining it in a state of high efficiency, training, discipline and morale and he shall for that purpose take all such steps as he may consider necessary, by way of tours, inspections, examination of records, calling for reports, framing regulations, issuing instructions and giving directive on all matters pertaining to the administration of the Force. He shall in particular guide and direct the supervisory officers and it shall be his duty to ensure that each supervisory officer maintains the Force in his charge at a high level of efficiency and discipline.

(2) The Director General shall keep himself in touch with the Chairman, Managing Directors and General Managers of the Public Sector Undertakings where the Force is deputed and post himself from time to time with the problems and needs of each such Undertakings in relation to the Force. He shall maintain close liaison with the Police and other authorities of the State so as to secure effective co-ordination between the State Police and the Force in regard to matters pertaining to the protection and Security of Public Sector Undertakings. He shall keep the Central Government duly informed of all matters of importance.

7. Duties of Sector Inspectors General in Central Industrial Security Force—(1) To exercise powers of Head of Department in the respective sectors for inclusion which may consist one or more zones in financial and administrative matters as provided under the various rules.

(2) To closely monitor the crime situations in the field units and adopt proper crime control measures in the respective Sectors.

(3) To exercise operational control of the Force, deployed under his charge including those in various Public Sector Undertakings and to render timely directions to the respective Zonal/Plant Deputy Inspectors General. This also includes deployment on Internal Security duties/Election duties etc.

(4) To guide and direct all concerned to ensure effective security arrangements in the Industrial Undertakings

(5) To establish and maintain liaison and coordination with the Chief Secretaries, Director General of Police/Inspector General of Police of the States and Heads/Chief Executives of the Public Sector Establishments.

(6) To carry out the inspections of Units in his sector as per the Circulars from Force Headquarters.

(7) To scrutinise the inspection reports conducted by the Zonal/Plant Deputy Inspectors General relating to various Units and monitoring of the compliance of short-falls pointed out therein,

(8) To conduct special enquiries within the Sector or elsewhere as and when so directed by Force Headquarters.

(9) To scrutinise and approve the tour programmes, inspection notes and monthly diaries of Zonal/Plant Deputy Inspectors General.

(10) To exercise powers for grant of leave as per the rules/instructions issued by Force Headquarters.

(11) To order postings/transfers of enrolled members of the Force within the sector.

(12) To ensure speedy disposal of departmental enquiry cases and close monitoring of Court cases.

(13) To ensure timely recovery of Central Industrial Security Force dues.

(14) To ensure proper training of the Force personnel under his charge.

(15) To look after and to take effective steps for the welfare of Force personnel under his charge to keep their morale high.

(16) To ensure timely action by Units on information/details asked for by Force Headquarters.

8. Duties of Deputy Inspector General—(1) For proper supervision of the Force, the Country shall be divided in zones. A Deputy Inspector General shall be the incharge of each zone. He shall be responsible for maintaining the Force in his charge in a state of high efficiency, training, discipline and morale. For this purpose, he shall inspect the Units and the Industrial Undertakings in Public Sector in his Zone where the Force is deputed at least twice a year and send his Inspection Reports to the Inspector General, giving details of the state of the Force and its administration.

(2) The Deputy Inspector General shall be readily available to the Commandants and shall aid, advice and control them. He shall keep in touch with the Chairman, Managing Directors and General Managers of the Undertakings in his Zone and shall also keep liaison with the State authorities with a view to secure full cooperation between the State Police and the Force in ensuring proper protection and security of the property of the Industrial Undertakings in the Public Sector in his Zone. He shall keep the Inspector General fully informed of all developments which need his attention normally all communications between the Commandant and Inspector General shall be channelized through the Deputy Inspector General though in cases of great urgency the Commandant may write to the Inspector General direct in which case, he shall endorse a copy to the Deputy Inspector General.

9. Duties of Managing Director and General Manager—The Force deputed to an Undertaking shall work under the general supervision, direction and control of the Managing Director of that Undertaking. The Commandant of the Force shall keep the managing director fully informed of all developments including the state of the Force. The Managing Director shall inspect the posts of the Force situated in his Undertaking at least once a year.

10. Duties of Commandant—(1) The Commandant shall be the head of the Unit. He shall be responsible for the efficiency, discipline and morale of the Unit and for the proper management of each branch of the Force under him. He shall periodically inspect the Units of the Force under his command. All orders to the Force under him shall emanate from him and all communications from the Force under him shall pass through him.

(2) The Commandant shall regularly inspect the detachments of the Force posted outside the headquarters and ensure that they remain in a high state of efficiency. He shall ensure that all enrolled members of the Force under him attend parade and refresher courses in turn according to a programme. When at headquarters, he shall attend the parade every Tuesday and Friday and hold the Orderly Room every Friday.

(3) The Commandant shall be responsible for the security of the Undertaking in which the detachment of his Units are posted. For that purpose he shall remain in close touch with the district as well as Police authorities and the heads of the various departments in the said Undertaking. He shall keep the Managing Director and the General Manager of the said undertaking as well as the Deputy Inspector General fully informed of all the developments and send them regular fortnightly reports as prescribed. Matters of urgent nature, however, shall be brought to their notice by the quickest possible means. He shall pay his personal attention to the working of the Intelligence wing and ensure that intelligence is efficiently collected and conveyed promptly to the Managing Director, General Manager and the Deputy Inspector General.

11. Duties of Deputy Commandant—(1) The Deputy Commandant shall assist the Commandant in the discharge of his duties; and where he is placed as head of the Unit, he shall discharge all the duties of a Commandant and shall exercise only those financial powers that are delegated to him under the relevant rules.

(2) The Deputy Commandant shall be responsible for the efficiency, discipline and morale of the personnel under him and shall also be responsible for the security of the undertaking or its part entrusted to him.

12. Duties of Assistant Commandant—The Assistant Commandant shall assist the Commandant and unless specifically directed to the contrary in the regulations framed for the purpose he shall perform all the functions of the Commandant when so required by the latter. He shall be responsible for the efficiency, discipline and morale of the personnel under him and shall also be responsible for the security of the Undertaking or its part entrusted to him.

CHAPTER—III

PROCEDURE OF ARREST, SEARCH, ETC.

13. Arrest—(1) In making an arrest, under sub-section (1) of Section 11 of the Act, the member of the Force shall actually touch or confine the body of the person to be arrested.

(2) If such person forcibly resists the endeavour to arrest him, or attempts to evade the arrest, the member of the Force may use all means necessary to effect the arrest. In case of use of force, it should be minimum, required in that particular situation.

(3) The person arrested shall not be subject to more restraint than necessary to prevent his escape.

(4) The member of the Force making the arrest, may search such person, and place in safe custody all articles including weapons, if any, other than necessary wearing apparels, found upon him. An inventory of all such articles shall be prepared in the presence of at least two respectable witnesses and in the presence of the arrested person and a copy of the inventory duly signed by the witnesses and the person conducting the search, shall be given to the person so arrested after obtaining due receipt.

(5) Such arrested person as well as the seized articles and its inventory shall be handed over to a police officer or at the nearest police station without avoidable delay alongwith a brief note giving the time, date and reasons of arrest.

14. Search—Whenever a search of a person and of his belonging is conducted under section 12 of the Act, an inventory shall be prepared in the presence of the two respectable witnesses and a copy of the inventory duly signed by the witnesses and the

person who conducted the search, shall be given to the person concerned after obtaining due receipt. The property so found on such search, shall also be sent to the police alongwith the person. If nothing is found on such search, a nil inventory statement duly signed shall be sent to the police alongwith the person.

15. Prescribed rank—The prescribed rank for the purposes of sub-section (1) of section 12 of the Act shall be the Head Constable.

CHAPTER—IV

RECRUITMENT TO THE FORCE

16. Powers of appointment—Subject to the provisions of the Act and these rules, appointments to the post of Inspector shall be made by the Deputy Inspector General concerned and to the ranks of Sub-Inspector, Assistant Sub-Inspector, Head Constable, Constable and Followers shall be made by the Commandant.

17. Conditions of eligibility for appointment to the Force—No person shall be eligible for appointment to the Force unless—

- (a) (i) he is a citizen of India; or
- (ii) he belongs to such categories of persons as may, from time to time be declared by the Central Government as being eligible for appointment to the Force;
- (b) he bears a good moral character,
- (c) he obtains a health certificate in the form prescribed in Appendix "C" certified by a Medical Officer of Central Industrial Security Force or any other Medical Officer or Assistant Surgeon belonging to Grade-1 of any Government Hospital or Dispensary.

18. Disqualification—No person,—(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with another person, shall be eligible for appointment to the Force;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so do, exempt any person from the operation of this rule.

CHAPTER—V

DIRECT RECRUITMENT

19. Name of the posts, their classification and scales of pay—The name of posts of members of the Force, their number and classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in the Recruitment Rules as amended from time to time.

20. Method of recruitment, age limits and other qualifications—The method of recruitment, age limits, qualifications and other matters relating to each of the said post shall be as specified in the recruitment rules as amended from time to time.

21. Agreement—Every enrolled member of the Force except those appointed on transfer on deputation shall execute at the time of his initial appointment an agreement in the form specified in Appendix "A".

22. Cadre—Each of the three branches mentioned in rule 3 shall form a separate cadre for the purpose of seniority, promotion and confirmation.

CHAPTER—VI

DEPUTATION

23. (1) (a) During the period of deputation, the officer on deputation shall be governed by the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder. Provided that the provisions of rules 58, 59 and 71 shall not apply to him.

(b) Without prejudice to the foregoing, every such officer shall be subject to the rules of discipline applicable to the corresponding rank to the Force.

(2) Save as aforesaid, the other terms and conditions of deputation shall be such as may be agreed upon between the lending authority and the Central Government.

(3) Notwithstanding anything contained in these rules, the Central Government or the Director General, as the case may be, may, without assigning any reason terminate the period of deputation of any officer at any time and such termination shall not be deemed to be a punishment.

CHAPTER—VII

PROMOTION

24. Promotion—Notwithstanding anything contained in these rules specially deserving Constable or Head Constable who have put in fifteen or twenty years of service may be promoted to the rank of Head Constable or Assistant Sub-Inspector as the case may be, on the basis of their service records by the Commandant with the approval of the Deputy Inspector General, but the total number of such promotion shall not exceed 10% of the posts which may be filled by the method of promotion.

25. Probation—(1) Every member of the Force except those appointed on deputation/absorption, shall be on probation for the period specified in relevant column of the Recruitment Rules:

Provided that in the absence of a specific order of confirmation or a declaration of satisfactory completion of probation, a member of the Force shall be deemed to be on probation:

Provided further that no member of the Force shall ordinarily be kept on probation for more than twice the period prescribed in respective recruitment rules.

(2) If during the period of probation the appointing authority is of the opinion that a member of the Force is not fit for permanent appointment, the appointing authority may discharge him from the Force after issue of notice of one month or after giving one month's pay in lieu of such notice, or revert him to the rank from which he was promoted or repatriate to his parent department as the case may be.

(3) On successful completion of probation by a member of the Force, the appointing authority shall pass an order confirming the member of the Force in the grade in which he joined the Force.

26. Termination—(1) where a notice is given by the Deputy Inspector General terminating the services of a probationer is terminated either on the expiry of the period of such notice or forthwith by payment of pay plus allowance or services are terminated by the appointing authority for his failure to pass the final examination of the initial training course, the Inspector General, if the said Deputy Inspector General or the appointing authority as the case may be subordinate to him, may on his own motion or otherwise, reopen the case and after making such enquiry he may (i) confirm the Action taken by the Deputy Inspector General or the appointing authority as the case may be; (ii) withdraw the notice; (iii) reinstate the probationer in service; or (iv) make such other order in the case as he may consider proper.

Provided that except in special circumstances, which should be recorded in writing, no case shall be reopened in writing, no case shall be reopened under this sub-rule after the expiry of three months.

(a) From the date of notice, in a case where notice is given.

(b) From the date of termination of service in a case where no notice is given.

(2) Where a probationer is reinstated in service under above rule, the order of reinstatement shall specify; (i) the amount of proportion of pay and allowances, if any, to be paid to the probationer for the period of his absence between the date of termination of his services and date of his reinstatement; and (ii) whether the said period shall be treated as a period spent on duty for any specified purpose or purposes.

(3) Where the Inspector General has terminated the service of a probationer, acting as appointing authority, all the powers prescribed in sub-rule (1) and (2) above shall be exercised by the Director General and where the Director General has issued the order of termination by the Central Government.

CHAPTER—VIII

SPECIAL PROVISIONS

27. Special provision for certain categories of persons—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Schedule Tribes, Exservicemen and other special categories of persons, in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

28. Power to relax—Notwithstanding, anything contained in the foregoing rules, where, in the interest of the formation and the due functioning of the Force it is necessary so to do relaxation under these rules (other than the requirement of being medically fit) may be made at the time of direct recruitment by the Director General :—

(i) Constable—any of the eligibility criteria.

(ii) Followers—Age limit only.

CHAPTER—IX

CONDITIONS OF SERVICE AND CONDUCT

29. **Manuals**—The Director General shall frame Training Manual, Establishment Manual as well as other manuals for administration of the Force with the approval of the Central Government.

30. **Solemn affirmation of allegiance**—On appointment, each recruit or cadet shall be required to solemnly affirm his allegiance in the form given in Appendix “B” and shall receive a certificate of appointment as prescribed in section 6 of the Act.

CHAPTER—X

PENALTIES AND PROCEDURE

31. **Rules governing discipline**—(1) Supervisory officers shall be governed by the rules applicable to the officers of the Central Government of corresponding class in respect of disciplinary proceedings.

(2) The enrolled members of the Force shall in such matters be governed by the rules in this Chapter.

32. **Disciplinary Authorities**—(1) The disciplinary authority in respect of an enrolled members of the Force for the purpose of imposing any particular penalty or the passing of any disciplinary order shall be the authority specified in this behalf in Schedule-I under whose administrative control the enrolled member is serving and shall include any authority mentioned in the said Schedule superior to such authority.

(2) Whenever an enrolled member of the Force is deployed for operational duty outside the place of his permanent posting then a supervisory officer under whose control such member has been so deployed shall be competent to place him under suspension. Such supervisory officer shall refer the matter to his disciplinary authority as mentioned in sub-rule (1).

(3) A disciplinary authority competent under Schedule-I to impose any of the penalties specified in clause (VI) to (x) of rule 34 may institute disciplinary proceedings against any enrolled member of the Force for imposition of any of the penalties specified in clause (i) to (v) of rule 34 notwithstanding that such disciplinary authority is not competent under Schedule-I to impose any such penalties.

33. **Suspension**—(1) The appointing authority or any authority to which it is subordinate or the disciplinary authority or any other authority empowered in that behalf by the President by general or special order may place an enrolled member of the Force under suspension—

- (a) where a disciplinary proceedings against him is contemplated or is pending; or
- (b) where a case against him in respect of any Criminal offence is under investigation, inquiry or trial; or
- (c) where in the opinion of the authority aforesaid, he engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the State :

Provided that where the order of suspension is made by an authority lower than the appointing authority, such authority shall forthwith report to the appointing authority the circumstances in which the order was made and obtain his approval within 30 days from the date of the order.

(2) An enrolled member of the Force shall be deemed to have been placed under suspension by an order of the appointing authority—

- (a) with effect from the date of his detention, if he is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding fortyeight hours;
- (b) with effect from the date of his conviction in the event of a conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding fortyeight hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction :

Explanation—The period of forty eight hours referred to in clause (b) of this sub-rule shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose, intermittent periods of imprisonment, if any, shall be taken into account.

(3) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon an enrolled member of the Force under suspension is set aside in appeal or on review under these rules and the case is remitted for further enquiry or action or with any other directions, the orders of his suspension shall be deemed to have continued in Force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall

remain in Force until further orders.

(4) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon an enrolled member of the Force is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision or a court of law and the disciplinary authority, on consideration of the circumstances or the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the enrolled member of the Force shall be deemed to have been placed under suspension by the appointing authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders.

(5) (a) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall continue to remain in Force until it is modified or revoked by the authority competent to do so.

(b) where an enrolled member of the Force is suspended or is deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceedings or otherwise) and any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that suspension, the authority competent to place him under suspension, may for reasons to be recorded by him in writing, direct that the enrolled member of the Force shall continue to be under suspension until the termination of all or any of such proceedings.

(c) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule may at any time be modified or revoked by the authority which made or is deemed to have been made the order or by any authority to which that authority is subordinate.

34. Nature of Penalties—The following penalties may, for good and sufficient reasons and as hereinafter provided, be imposed on an enrolled member of the Force, namely :—

Major Penalties—

- (i) dismissal from Service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government;
- (ii) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;
- (iii) compulsory retirement;
- (iv) reduction to a lower time scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government servant to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which enrolled member of the Force was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;
- (v) save as provided for in clause (viii) below—reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the enrolled member will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will have the effect of postponing the future increments of his pay.

Minor penalties—

- (vi) Censure;
- (vii) withholding of his promotion;
- (viii) Reduction to a lower stage in the time scale of pay for a period of not exceeding three years, without cumulative effect and not adversely affecting his pension;
- (ix) withholding of increment of pay;
- (x) fine to any amount not exceeding of 7 days' pay.

Explanation—The following shall not amount to a penalty within the meaning of this rule, namely :—

- (a) withholding of increment of an enrolled member for failure to pass a departmental examination in accordance with the rules or orders or the terms of his appointment;
- (b) stoppage of increment of an enrolled member at the efficiency bar in a time scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar;
- (c) non-promotion of an enrolled member whether in a substantive or officiating capacity, after consideration of his case, to a rank or post for promotion to which he is eligible;
- (d) reversion of an enrolled member officiating in a higher rank or post to a lower rank or post, on the ground that he is considered after trial, to be unsuitable for such higher rank or post or on any administrative grounds unconnected with his conduct;

- (e) reversion of an enrolled member appointed on probation to any other rank or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation;
- (f) replacement of the services of an enrolled member whose services had been borrowed from any department of the Central Government or State Government or any authority under the Central Government or the State Government at the disposal of the Central Government or the State Government or the authority from which the services of such enrolled member had been borrowed;
- (g) compulsory retirement of an enrolled member in accordance with the provisions relating to his superannuation or retirement;
- (h) Termination of service - (i) of an enrolled member appointed on probation during or at the end of the period of his probation, in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation; or
 - (ii) of a temporary enrolled member in accordance with the provisions of rule 25; or
 - (iii) of an enrolled member, employed under an agreement, in accordance with the terms of such agreement;
- (I) treatment of absence from duty as "dies-non" ordered by a competent authority under rule 55:

35. Petty punishments—Head Constable, Constable and Follower may also be awarded, as punishment, extra drill, guard, fatigue or other duty for a term not exceeding fourteen days.

Explanation—Petty punishments shall ordinarily be awarded in Orderly room as provided in rule 38 of this Chapter.

36. Procedure for imposing major penalties—(1) Without prejudice to the provisions of the Public Servants (Inquiry) Act, 1850 (37 of 1850), no order imposing on an enrolled member of the Force any of the penalties as specified in clauses (i) to (v) of rule 34 shall be made except after an inquiry held, as far as may be, in the manner hereinafter provided.

(2) Whenever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against an enrolled member of the Force, it may itself inquire into, or appoint an authority to inquire into the truth thereof.

Explanation—Where the disciplinary authority itself holds the inquiry, any reference in sub-rule (7) to (18) of this rule shall be construed as a reference to the disciplinary authority.

(3) Where it is proposed to hold an inquiry against an enrolled member of the Force under this rule the disciplinary authority shall draw up or cause to be drawn up—

- (i) the substance of the imputation of misconduct or misbehaviour into definite and distinct articles of charge;
- (ii) a statement of the imputation of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge, which shall contain;
 - (a) a statement of all relevant facts including any admission or confession made by the enrolled member of the Force,
 - (b) a list of documents by which, and a list of witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained.

(4) The disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the enrolled member of the Force a copy of the articles of charge, the statement of imputations of misconduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article of charge is proposed to be sustained and shall require the enrolled member of the Force to submit, within such time as may be specified, a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person.

(5) (a) On receipt of the written statement of defence, the disciplinary authority may itself inquire into such of the articles of charge as are not admitted, or if it considers it necessary to do so, appoint under sub-rule (2), an inquiring authority not below the rank of Inspector for the purpose, and where all the articles of the charge have been admitted by the enrolled member of the Force in his written statement of defence, the disciplinary authority shall record its findings on each charge after taking such evidence as it may think fit and shall pass an order in the manner laid down in sub-rule (20) to (22).

(b) If no written statement of defence is submitted by the enrolled member of the Force, the disciplinary authority may itself inquire into the articles of charge, or may, if it considers it necessary to do so, appoint, under sub-rule (2) an inquiring authority for the purpose.

(6) The disciplinary authority shall, where it is not the inquiring authority, forward to the inquiring authority—

- (i) a copy of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;
- (ii) a copy of the written statement of defence, if any, submitted by the enrolled member of the Force;
- (iii) a copy of the statement of witnesses, if any, referred to in sub-rule (3);
- (iv) evidence proving the delivery of the documents referred to in sub-rule (3) to the enrolled member of the Force.

(7) The enrolled member of the Force shall appear in person before the inquiring authority on such day and at such time and place, within ten working days from the date of receipt by him of the article of charge and the statement of imputation of misconduct or misbehaviour as the inquiring authority may, by notice in writing, specify in this behalf or within such further time, not exceeding ten days as the inquiring authority may allow.

(8) (a) The enrolled member of the Force so charged may be permitted by the inquiring authority to present his case with the assistance of any other Member of the Force posted at the place of inquiry. He will give three choices for his defence assistance and the controlling officer will depute any one of the three indicated by him;

(b) The enrolled member of the Force can not have more than three cases in hand in which he is rendering defence assistance. However, the controlling authority of such persons who is sought to be engaged may refuse permission for his working as defence assistant if the public interest so demands.

(9) If the enrolled member of the Force who has not admitted any of the article of charge in his written statement of defence or has not submitted any written statement of defence, appears before the inquiring authority, such authority shall ask him whether he is guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the enquiring authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the enrolled member of the Force thereon.

(10) The inquiring authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the enrolled member of the Force pleads guilty.

(11) The inquiring authority shall, on receipt of the notice for the discovery or production of documents forward the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the documents are kept, with a requisition for the production of the documents by such date as may be specified in such requisition.

(12) On receipt of the requisition referred to in sub-rule (11), every authority having the custody or possession of the requisitioned documents shall produce the same before the inquiring authority :

Provided that if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that the production of all or any of such documents would be against the public interest or security of the state, it shall inform the inquiring authority accordingly and the inquiring authority shall, on being so informed, communicate the information to the enrolled member of the Force and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of documents.

(13) The inquiring authority shall direct the enrolled member of the Force, if he so wishes for the purpose of preparing his defence to inspect and take extracts from such official records as specified in list referred to in sub-rule (3) within 5 days from the date of such order. The disciplinary authority may refuse to grant access of any such documents, if that authority is of the opinion for the reasons to be recorded in writing, that such records are not relevant for the purpose or these are against the public interest.

(14) The inquiring authority shall, if the enrolled member of the Force fails to appear within the specified time or refuses or omits to plead, proceed to record the evidence by which the articles of charge are to be sustained.

(15) On the date fixed for the inquiry, the inquiring authority shall examine the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved. The enrolled member of the Force shall be entitled to cross-examine the witnesses examined in support of the charge. The inquiring authority may also put such questions to the witnesses as it thinks fit.

(16) The enrolled member of the Force may give the name of his defence witnesses who, shall be examine. If the inquiring authority declines to examine any defence witnesses on the ground that his evidence is not relevant or material, it shall record its reasons for the same in writing.

(17) The enquiring authority may after the enrolled member close his case, and shall generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling him to explain any circumstances appear-

ing in the evidence against him. The enrolled member may also be permitted to file the written statement of his defence, if he so desires within 7 days.

(18) If the enrolled member to whom a copy of the articles of the charge has been delivered, does not submit written statement on or before the date specified for the purpose or does not appear in person before the inquiring authority or otherwise fails or refuses to comply with provisions of the rule, the inquiring authority may hold the enquiry ex-parte.

(19) (i) After the conclusion of the inquiry, a report shall be prepared and it shall contain-

- (a) the article of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;
- (b) the defence of the enrolled member in respect of each article of charge;
- (c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge;
- (d) the findings on each article of charge and reasons thereof-

Explanation-If, in the opinion of the inquiring authority the proceedings of the inquiry establish any article of charge different from the original article of the charge, it may record its findings on such article of charge;

Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the enrolled member has either admitted the fact on which such article of charge is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

(ii) The inquiring authority, where it is not itself the disciplinary authority shall forward to the disciplinary authority the records of enquiry which shall include-

- (a) the report prepared by it under clause (i);
- (b) the written statement of defence, if any, submitted by the enrolled member;
- (c) the oral and documentary evidence produced in the course of inquiry;
- (d) written brief, if any, filed by the enrolled member during the course of the inquiry; and
- (e) the orders, if any, made by the disciplinary authority and the inquiry authority in regard to the enquiry.

(20)(i) where a disciplinary authority competent to impose any of the minor penalties and not competent to impose any of the major penalties specified in rule 34 has itself inquired into or cause to be inquired into the articles of any charge and that authority having regard to his own finding or having regard to his decision on any of the findings of any inquiring authority appointed by it, is of the opinion that the major penalty specified in rule 34 should be imposed upon the enrolled member, that authority shall forward the records of the inquiry to such disciplinary authority as is competent to impose any of the major penalties.

(ii) The disciplinary authority to which the records are so forwarded may act on the evidence on the record or may remit the case to the disciplinary authority from whom the records were forwarded or the inquiring authority, as the case may be, for further inquiry and report on any point.

(21)(i) The disciplinary authority, if it is not itself the inquiring authority, may, consider the records of inquiry and record its findings on each charge. The disciplinary authority may, for reasons to be recorded by it in writing remit the case to the inquiring authority for further inquiry and report and the inquiring authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of this rule as far as may be.

(ii) The disciplinary authority shall, if it disagrees with the findings of the inquiring authority on any article of charge, record its reasons for such disagreement and record its own findings on such charge if the evidence on record is sufficient for the purpose.

(22)(i) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge is of the opinion that any of the minor penalties specified in rule 34 should be imposed on the enrolled member, it shall notwithstanding anything contained in rule 37 make an order imposing such penalty;

(ii) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge and on the basis of evidence adduced during the course of inquiry, is of the opinion that any of the major penalties specified in rule 34 should be imposed on the enrolled member, it shall make an order imposing such penalties and it shall not be necessary to give the enrolled member any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed.

37. Procedure for imposing minor penalties-(1) No order imposing any of minor penalties specified in rule 34 shall be made except after-

(a) informing the enrolled member in writing of the imputations of misconduct or misbehaviour on which it is proposed to be taken and giving him a reasonable opportunity of making such representation as he wishes to make against the proposal;

(b) holding an inquiry, if the disciplinary authority so desires, in the manner laid down in sub-rules (3) to (22) of rule 36;

(c) taking the representation, if any submitted by the enrolled member under clause (a) and the record of inquiry, if any, held under clause (b) into consideration; and

(d) recording the findings on each imputation of misconduct or misbehaviour;

(2) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-rule (1), if in a case it is proposed after considering the representation, if any, made by the Government servant under clause (a) of that sub-rule to withhold increments of pay and such withholding of increments is likely to affect adversely the amount of pension payable to the Government Servant or to withhold increments of pay for a period exceeding 3 years or to withhold increments of pay with cumulative effect for any period an inquiry shall be held in the manner laid down in sub-rule (3) to (22) of Rule 36 before making any order imposing on the enrolled member of the Force any such penalty.

(3) The records of the proceedings in such cases shall include - (i) a copy of the intimation to the enrolled member so charged of the proposal to take action against him;

(ii) a copy of the statement of imputation of misconduct or misbehaviour delivered to him;

(iii) his representation, if any;

(iv) the evidence produced during the enquiry, if any;

(v) the findings on each imputation of misconduct or misbehaviour; and

(vi) the orders on the case together with the reasons therefor.

38. Procedure for imposing petty punishment - Petty breaches of discipline and trifling cases of misconduct by the enrolled members of the Force not above the rank of the Head Constable shall be inquired into and disposed of in the Orderly room. The punishment enumerated in rule 35 may be awarded, making a record of the summary proceedings in the Orderly Room register which shall be maintained for keeping record of such punishments. There shall be no appeal against the punishment awarded in the Orderly Room.

39. Special procedure in certain cases—

Notwithstanding anything contained in rules 36 to 38 -

(i) where any penalty is imposed on an enrolled member of the Force on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge; or

(ii) where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these rules, or

(iii) where the President is satisfied that in the interest of the security of the state, it is not expedient to hold any inquiry in the manner provided in these rules, the disciplinary authority may consider the circumstances of the case and make such orders thereon as it deems fit;

Provided that the enrolled member of the Force may be given an opportunity of making representation against the penalty proposed to be imposed before any order is made in case under clause (i).

40. Provisions regarding enrolled members of the Force borrowed from State Governments etc. - (1) where an order of suspension is made or a disciplinary proceeding is conducted against an enrolled member of the Force whose services have been borrowed from another department of the Central Government or from a State Government or an authority subordinate thereto, the authority lending his services (hereinafter in these rules referred to as the 'lending authority') shall forthwith be informed of the circumstances leading to the order of suspension the enrolled member of the Force or the commencement of the disciplinary proceedings, as the case may be.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceedings conducted against such - an enrolled member of the Force if the disciplinary authority is of the opinion that any of the penalties specified in clause (vi) to (x) of rule 34 should be imposed on him, it may, subject to the provisions of sub-rule (22) (i) of rule 36 and after consultation with the lending authority, pass such orders on the case as it may deem necessary -

(i) provided that in the event of difference of opinion between the borrowing authority and the lending authority, the services of such enrolled member of the Force shall be replaced at the disposal of the lending authority;

(ii) if the disciplinary authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (v) of rule 34 should be imposed on the enrolled member of the Force, it shall replace the services of such enrolled member of the Force at the disposal of the lending authority and transmit to it the proceedings of the enquiry for such action as it may deem necessary.

41. Provisions regarding enrolled member of the Force lent to state Government etc.—(1) where the services of an enrolled member of the Force are lent to another department of the Central Government or to a State Government or other authority herein-after in this rule referred to as "borrowing authority" the borrowing authority shall have the powers of the appointing authority for the purpose of placing such enrolled member of the Force under suspension and of the disciplinary authority for the purpose of conducting a disciplinary proceeding against him;

Provided that the borrowing authority shall forthwith inform the authority which lent the services of such enrolled member of the Force hereinafter in this rule referred to as 'the lending authority' of the circumstances leading to the order of suspension of such enrolled member of the Force or the commencement of the disciplinary proceeding, as the case may be;

(2) In the light of findings in the disciplinary proceedings conducted against the enrolled member of the Force;

(i) If the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (vi) to (x) of Rule 34 should be imposed on such a member, it may, after consultation with the lending authority, make such orders on the case as it may deem necessary;

Provided that in the event of difference of opinion between the borrowing authority and the lending authority, the services of such enrolled member of the Force shall be replaced at the disposal of the lending authority;

(ii) If the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (v) of rule 34 should be imposed on the enrolled member, it shall replace his services at the disposal of lending authority and transmit the proceedings of the enquiry and thereupon the lending authority may, if it is a disciplinary authority, pass such orders thereon as it may deem necessary, or if he is not a disciplinary authority, submit the case to the appropriate disciplinary authority which shall pass orders on the case as it may deem necessary;

Provided that before passing any such order the disciplinary authority shall comply with the provisions of sub-rule (22) of rule 36.

Explanation - The disciplinary authority may make an order under this clause on the record of the inquiry transmitted to it by the borrowing authority or after holding such further inquiry as it may deem necessary, as far as may be in accordance with rule 36.

42. Reduction in rank etc. - No enrolled member of the Force shall be reduced to a rank lower than that to which he was first appointed to the service nor shall be reduced permanently in the sense that he may never be eligible for re-promotion however meritorious his subsequent service may be. When reduction to a lower rank class, grade or a lower time scale or a lower stage in the time scale is ordered, the order shall also specify the position in the lower rank on such reduction as well as the period for which the reduction shall hold good.

43. Withholding of increment - In case of withholding of increment as a punishment, the order shall state the period for which the increment is to be withheld and whether it shall have the effect of postponing further increments.

CHAPTER-XI

APPEALS, REVISIONS AND PETITIONS

44. Appeal against order of suspension - An enrolled member of the Force may appeal against the order of suspension to the authority, to which the authority which made or is deemed to have made the order is immediately subordinate.

45. Orders against which no appeal lies-Notwithstanding anything contained in this chapter, no appeal shall lie against -

(i) any order of interlocutory nature or of the nature of step-in-aid or the final disposal of disciplinary proceedings other than an order of suspension; and

(ii) any order passed by an inquiring authority in the course of inquiry under rule 36.

46. Appeal against order imposing penalties—(1) An enrolled member may prefer an appeal against all or any of the following orders, namely :—(i) an order of suspension made or deemed to have been made under rule 33;

(ii) an order imposing any of the penalties specified in rule 34, made by the disciplinary authority or by any appellate or revising authority.

(2) Such appeal shall be made to the authority immediately superior to the authority who has imposed the penalty.

NOTE : (i) Appeal against the order of Deputy Inspector General shall lie to the Sector Inspector General and against the order of the Sector Inspector General to the Director General.

(ii) Appeal against the order of the Deputy Inspector General at Force Headquarters including Deputy Inspector General (Training and Fire) shall lie to Inspector General (Headquarters) and against the order of Inspector General (Headquarters) to the Director General.

(iii) Appeal against the order of the Director General shall lie to the Central Government.

(iv) Where the person who made the order appealed against becomes, by virtue of his subsequent appointment or otherwise the appellate authority in respect of such order, an appeal against such order shall lie to the authority to whom such person is immediately subordinate.

(3) There shall be no second appeal. But when the appellate authority imposes a penalty higher than the one appealed against, an appeal shall lie to the authority next superior to the appellate authority.

47. **Period of limitation for appeals** - No appeal under these rules shall be entertained unless it is submitted within a period of 30 days from the date on which the appellant receive a copy of the order appealed against.

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

48. **Form and contents of appeal-** (1) Every enrolled member preferring an appeal shall do so separately in his own name.

(2) The appeal shall be addressed to the authority to whom the appeal lie, shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies, shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself.

49. **Submission of Appeals-** (1) The appellant shall submit such appeal to the authority which made the order appealed against :

Provided that if the appellant at the time of submitting such appeal is not serving under that authority, shall submit the appeal to the authority under whom he is serving and that authority shall forward it forthwith to the appropriate authority. If the appellant is not in service, he shall submit his appeal direct to the appellate authority, a copy of the appeal will also be forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against.

50. **Withholding of appeals** - (1) The authority which made the order appealed against, may withhold the appeal if - (i) it is an appeal against an order for which no appeal lies under rule 45; or

(ii) it is not in conformity with the provisions of rule 48; or

(iii) it is not submitted within the period specified in rule 47 and no sufficient cause is shown for the delay ; or

(iv) it is repetition of any appeal already decided and no new facts of circumstances are adduced;

Provided that an appeal withheld on the ground only that it was not in conformity with provisions of rule 48, shall be returned to the appellant and if re-submitted within 30 days thereof, after compliance with the said provisions, shall not be withheld.

(2) Where an appeal is withheld on any grounds under sub-rule(1) of this rule, the appellant shall be informed of the facts and the reasons therefor.

51. **Transmission of appeals** - The authority which made the order appealed against, shall on receipt of such appeal, forward the same together with the relevant records, to the appellate authority without any avoidable delay and without waiting for any directions from the appellate authority unless the appeal is withheld under rule 50.

52. **Consideration of appeals** - (1) In the case of an appeal against an order of suspension, the appellate authority shall consider whether in the light of the provisions of rule 31 and having regard to the circumstances of the case, the order of suspension is justified or not and confirm or revoke the order accordingly.

(2) In the case of an appeal against the order imposing any of the penalties specified in rule 34, or enhancing any penalty imposed under the said rules, the appellate authority shall consider -

(a) Whether the procedure laid down in these rules has been complied with and if not whether such non-compliance has resulted in the violation of any provisions of the Constitution of India or in the failure of justice;

(b) Whether the findings of the disciplinary authority are warranted on the basis of the evidence on the record; and

- (c) whether the penalty or the enhanced penalty imposed is excessive, or adequate, or inadequate and pass orders;
- (i) Confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty; or
- (ii) remitting the case to the authority which imposed or enhanced the penalty, or to any other authority with such directions as it may deem fit in the circumstances of the case :

Provided that—

- (i) If such enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (i) to (v) of rule 34 and an inquiry under rule 36 has not already been held in the case, the appellate authority shall, subject to the provisions of rule 39, itself hold such an inquiry or direct that such inquiry be held in accordance with rule 36 and thereafter on a consideration of the proceedings of such inquiry make such orders as it may deem fit; and
- (ii) If the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clause (i) to (v) of rule 34 and an inquiry under rule 36 has already been held in the case, the appellate authority shall make such orders as it may deem fit.

53. Implementation of orders in appeal—The authority which made the order appealed against shall give effect to the orders passed by the appellate authority.

54. Revision—Any authority superior to the authority making the order may either on his own motion or otherwise call for the records of any inquiry and revise any order made under these rules, and may—

- (a) confirm, modify or set aside the order; or
- (b) confirm, reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order, or impose any penalty where no penalty has been imposed; or
- (c) remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing such authority to make such further enquiry as it may consider proper in the circumstances of the case; or
- (d) pass such order as it may deem fit, within six months of the date of communication of the order propose to be revised;

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by any revisioning authority unless the Government servant concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed and where it is proposed to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (v) of rule 34 or to enhance the penalty imposed by the order sought to be revised to any of the penalties specified in those clauses, and if any, inquiry under rule 36 of Central Industrial Security Force Rules, 1969 has not already been held in the case no such penalty shall be imposed except after an enquiry in the manner laid down in the aforesaid rules.

2. The provisions of rule 52 relating to appeals shall apply so far as may be to such orders in revision.

3. Orders and instructions issued by the Central Government on this subject from time to time shall be applicable mutatis mutandis as applicable under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules 1965.

55. Dies-non—Notwithstanding anything contained in these rules a disciplinary authority while passing final order to impose a penalty upon an enrolled member of the Force or an appellate authority or a revising authority may, on reinstatement of an enrolled member of the Force in service after setting aside a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement without exonerating such enrolled member of the Force of the charges which resulted in any of these penalties, after giving an opportunity to the enrolled member of the Force concerned to show cause against such action and for reasons to be recorded in writing, order that the intervening period between the date of dismissal, removal or compulsory retirement as the case may be and the date of reinstatement be treated as dies-non for purposes of service.

56. Petitions—(1) Any enrolled member of the Force may submit a petition in respect of any matter connected with his official position in which his personal interests are involved other than a matter covered by the rule relating to appeals and revision.

(2) Each such enrolled member of the Force shall submit a petition solely relating to his individual case.

(3) Joint petitions of any kind whatsoever shall not be taken notice of and submission of such petitions shall be deemed to be an act of indiscipline.

(4) Such petition shall be in proper form and not couched in improper language and be submitted to the immediate superior even if the petitioner be on leave at the time. A petition submitted in contravention of this rule shall be summarily rejected.

(5) Such immediate superior shall submit it through his immediate superior to the authority competent to dispose it of. An officer superior to him may withhold any such petition if it is couched in intemperate language or is otherwise improperly written, in which case he shall inform the petitioner in writing that his petition has been withheld.

(6) In any subsequent petition to the competent authority, the petitioner shall also attach to his petition a copy of the order on his previous petition as communicated to him by his immediate superior officer.

57. Other methods forbidden—The supervisory officers and enrolled members of the Force are forbidden from resorting to any method other than that prescribed in these rules for pressing their claims or for obtaining redress of alleged grievances or reversal, any such attempt on their part shall be deemed to be an act of indiscipline.

CHAPTER—XII

MISCELLANEOUS

58. Resignation—(1) The appointing authority may during the period of probation or thereafter permit any member of the Force to resign from his post with effect from such date as may be specified in the order accepting his resignation:

Provided that before acceptance of resignation of any such member of the force up to the period of ten years from the date of appointment in the Force, for reasons other than accepting a job elsewhere for which cadre clearance has been given, shall be required to refund the cost of training imparted to him in the Force or a sum equal to three months' pay and allowances, whichever is more.

(2) The resignation of a member of the Force who is under trial or whose conduct is under inquiry may be refused.

59. Discharge Certificate—Whenever a member of the Force ceases to be such member for any reason whatsoever, a discharge certificate in the Form specified in Appendix "D" annexed to these rules shall be given to him.

60. Surrender of certificate of appointment—Every enrolled member ceasing to be a member of the Force shall surrender to his immediate superior his certificate of appointment which shall thereupon be submitted to the Commandant.

61. Free accommodation—(1) Normally, the undertaking where the Force has been deputed shall provide accommodation in the township itself to all Supervisory Officers and at the rate of 45 per cent married and 55 per cent unmarried or as amended by the Central Government from time to time, to the enrolled members of the Force.

(2) The accommodation to the enrolled member of the Force shall be rent-free but where such facilities are not available, they shall get house rent allowance in lieu thereof as applicable to other Central Government Employees.

(3) The members of the Force shall also get compensation in lieu of married accommodation in terms of orders issued by the Government from time to time in this respect. The compensation shall be payable to that percentage of members of the Force who are entitled to get married accommodation minus those members of the Force who are allotted accommodation by the Undertaking.

(4) Supervisory Officer of the Force who is provided accommodation by the public sector undertakings or allotted accommodation by Directorate of Estate will pay licence fee to the public sector undertakings at the rates as applicable to their own employees or the licence fee as fixed by the Central Government for general pool accommodation from time to time with reference to plinth area of accommodation as the case may be.

62. Medical facilities—Members of the Force shall be entitled to the facilities of the Central Government Health Scheme and in places where these facilities are not available, they shall be governed by the Central Civil Services (Medical Attendant) Rules, 1944;

Provided that when they are deployed in a Public Sector Undertaking;

- (i) in a case where such public sector undertaking provides medical facilities to its employees, such members of the Force shall be entitled to avail such facilities free of charge; and
- (ii) if such facilities are not available, the authorised medical attendant for such members of the Force will be as provided in Central Civil Services (Medical Attendant) Rules, 1944.

63. Leave—The Supervisory Officers and members of the Force shall be governed by the Leave Rules as are applicable to employees of the Central Government, excepting that they shall be entitled to fifteen days Casual Leave in a calendar year in respect of field formation where no specific working hours in a day or working weeks are prescribed and entitlement of Casual leave in static formation like Force Head Quarters, Sector Head Quarters etc. of Central Industrial Security Force will be 8 days in a calendar year as per Ministry of Home Affairs' Office Memorandum No. 27012/6/98/PF.I/419 dated 7-7-2000. The Regularisation of leave will be subject to orders issued by Central Government from time to time.

64. Recall from Leave—The Supervisory officers and enrolled member of the Force on leave may be recalled at any time by the authority empowered to sanction their leave. They may be directed to report for duty either at Headquarters or to proceed direct to the place at which their services are required.

In either case, travelling allowance as on tour (by shortest route) for the return journey may be allowed to them at the discretion of the authority recalling them from leave.

65. Free leave Pass and Leave Travel Concession—(1) Free leave Pass and leave travel concession shall be admissible to the members of the Force of and below the rank of Head Constable as follows, namely—

(a) when living away from their families one free leave pass every year from places of duty to the railway stations nearest to their towns and return, subject to the leave travel concession for their families in a block period of two years.

(b) In case they are living with their families and propose to avail themselves of leave travel concession for their families also, they shall be entitled to free leave pass to home towns and return for self only once in two years and leave travel concession (once in a block period of two years) to the family members under the normal leave travel concession Rules applicable to other Central Government Employees.

(c) Free leave pass when proceeding on medical leave of duration of not less than one month, provided it is certified that the illness or injury which necessitated medical leave was not brought about by any fault or negligence on the part of the member of the Force.

(d) Leave Travel Concession once in four years for self and family members to travel to any place in India as admissible to other Central Government Employees;

Provided that the leave travel concession admissible under clause (d) shall be in lieu of the free leave pass admissible under clause (a) and the leave travel concession and free leave pass admissible under clause (b).

(2) Supervisory officers and members of the Force of and above the rank of Assistant Sub-Inspector, shall be eligible to the same leave travel concession to which the other Central Government employees are eligible pursuant to the orders of the Central Government in this behalf.

66. Power to grant monetary rewards—Monetary rewards may be granted to the enrolled members of the Force non-gazetted Government Servants, employees and workers of the industrial undertakings and members of the public in accordance with rule 67, 68 and 69.

67. Eligibility for monetary rewards—(1) Monetary rewards may be granted only to the enrolled members of the Force for—

- (a) doing outstanding work, requiring special courage, skill or initiative such as—
 - (i) the arrest of a criminal; or
 - (ii) Securing of information leading to the detection of a crime or matters connected there with; or
 - (iii) making exceptionally good enquiries; or
 - (iv) an encounter with a criminal, in connection with the protection, safeguard and security of an industrial undertaking;
- (b) doing work of a less outstanding nature but requiring prompt, honest and intelligent observance of, and obedience to order so as to be of material assistance in the protection, safeguard and security of an industrial undertaking;
- (c) doing extra hard work in connection with the protection, safeguard and security of industrial undertaking;
- (d) smartness, markmanship, diligence, praiseworthy attention to the employees and workers of the industrial undertakings or to the persons who visit the industrial undertakings on business or for any other purpose which, in exceptional cases, is calculated to promote the efficiency of the Force.

(2) Monetary rewards in the form of books or articles of value not exceeding one thousand rupees for each prize may also be granted to enrolled members of the Force for proficiency during training for every batch of trainees who pass out of the Training College or Training Centre, as specified below :—

I Prize—for all round efficiency, First Rank;

II Prize—for all round efficiency, second rank;

III Prize—for proficiency in parade, musketry and sports.

(ii) Monetary rewards shall not be granted on request.

Explanation—For the removal of doubts, it is hereby declared that it shall be permissible to grant also the III Prize to a trainee who has been granted I Prize or II Prize.

(3) Monetary rewards may be granted to the non-gazetted Government servants, employees and workers of the industrial undertakings and the members of the public as an incentive for assisting the Force.

- (i) in the detection of any serious case, or
- (ii) in the apprehension of an offender, or
- (iii) in resisting a criminal or an anti-social elements; or
- (iv) for any other purpose, which is for the better protection, safeguard and security of the industrial undertakings.

Explanation—For the removal of doubts, it is hereby declared that for the purposes of this rule—

- (i) 'general good work' shall not be a ground for the grant of monetary rewards.
- (ii) monetary rewards shall not be granted on request.

68. Authorities competent to grant monetary rewards—(1) The Supervisory officers are empowered, subject to the budget provisions of the Force, to offer and grant monetary rewards under rule 67 as prescribed by the Central Govt. from time to time.

(2) A monetary reward under rule 67 shall be granted by an Officer competent to grant the same if he is of opinion, for reasons to be recorded in writing that the person fulfils the requirements in this behalf.

(3) The order granting such monetary reward shall indicate the reasons therefor and the provisions of rule 67 under which it is granted.

69. Monetary rewards offered by the Managing Director of the industrial undertakings—A supervisory officer of the Force may permit an enrolled member of the Force to accept monetary reward offered by a Managing Director of an industrial undertaking for a purpose relatable to sub-rule (1) of rule 67.

70. Benefits on account of risk of "office"/special Risk of "office"—In these matters, supervisory officer and enrolled members of the Force shall be governed by Central Civil Services (Extra Ordinary Pension) Rules as amended from time to time.

71. Superannuation etc.—The rules relating to superannuation pension, provident fund and gratuity of supervisory officers and enrolled members of the Force shall be the same as those applicable to the Central Government employees.

72. Transfer—(1) Transfers of members of the Force may be made as under—

- (i) of supervisory officers, by the Director General;
- (ii) of and upto the rank of Head Constable from one unit to another unit under the administrative control of one Commandant, by the Commandant;
- (iii) of the enrolled members of the Force from one Unit to another within the Zone by the Deputy Inspector General of that Zone; and
- (iv) of the enrolled members of the Force from one unit to another unit within the sector by the Deputy Inspector General of that sector.
- (v) of the enrolled members of the Force from one unit or zone to another in the entire Force by the Inspector General of Force Headquarters.

(2) An authority superior to the authority competent to sub-rule (1) may make an order of transfer, annul, change or modify any order of transfer made under sub-rule (1).

73. Payment of charges—The charges payable by an industrial undertaking in public sector for the deputation of supervisory officers and enrolled members of the Force under section 14 of the Act to such undertaking, shall be paid for such periods and in such manner as the Central Government may from time to time specify.

Explanation—For the purposes of this rule, charges payable by an industrial undertaking in public sector shall include—

- (i) the pay and allowances, leave salary contribution and pension contribution payable to officers and enrolled members of the Force deputed to that undertaking;
- (ii) the cost of clothing, equipment, transport, arms and ammunitions and other accoutrements necessary for the proper discharge of the functions of such officers and members; and

- (iii) the amount which the Central Government may, having regard to the number of officers and members of the Force deputed to the industrial undertaking, determine from time to time, as the proportionate amount being payable by the industrial undertaking towards the cost of maintaining the Headquarters and other establishments of the Force.

74. Non-applicability of rules in certain cases—(1) These rules shall not apply to enrolled members of the Force taken on contract who shall be governed by the conditions of their contract.

(2) Nothing in these rules shall be deemed to preclude the President—

- (a) from making any appointment to the Force which he may consider necessary, or
- (b) from passing any order or revising, whether on his own motion or otherwise, any order passed under these rules by any subordinate authority.

75. Award of Director General's Commendation Disc -

(1) Director General's Commendation Disc will be awarded to the CISF personnel on the following grounds :

- (a) for conspicuous achievement during operations.
- (b) commendable work in natural calamities.
- (c) outstanding achievement in sports for the country at international level.
- (d) Any innovation which may bring significant improvement in the working of the Force.
- (e) Clean and good record of service for 15 years.
- (f) Accident free driving and good record for a continuous period of 20 years.
- (g) for being graded "AX" in Army courses of 12 weeks duration or more.
- (h) for any conspicuous efforts in processing of difficult cases.
- (i) for any conspicuous work which may be considered of a commendable nature.
- (j) Recovery of property worth more than Rs.20,000 in case of Constable to Head Constable and more than Rs. 50,000 in case of Assistant-Sub-Inspectors to Inspectors and more than Rs. 1,00,000 in case of Gazetted Officer's. The property so recovered should not be of unclaimed nature.
- (k) Outstanding action in dealing with terrorists/Criminals which does not call for award of a gallantry medal.
- (l) standing first in Force level professional courses or standing 1st, 2nd or 3rd in an Inter-Force level training course.
- (m) Personnel who have been promoted out of turn owing to some outstanding work can also be considered.
- (2) Detailed instructions on this subject shall be issued separately from time to time with the approval of Central Government.

76. Ministerial staff - Ministerial staff (Civilian) shall be governed by the recruitment rules framed under article 309 of the Constitution of India.

Other conditions of service - The members of the Force shall, in respect of all matters regarding conditions of service for which no provision or insufficient provisions have been made in these rules be governed by the rules and orders for the time being applicable to officers holding corresponding posts in the Central Government in respect of such matters.

CHAPTER - XIII

MAGISTERIAL POWER FOR THE PURPOSE OF INQUIRING INTO OR TRYING ANY OFFENCE COMMITTED BY AN ENROLLED MEMBER OF THE FORCE AND THE OFFENCES PUNISHABLE UNDER THIS ACT.

78. Magisterial Powers - For the purpose of inquiring into or trying offences specified in sub-section (1) of Section 18 of the Act and in respect of all matters incidental to such inquiry or trial of such offences, every officer holding rank of Commandant or equivalent as mentioned in sub-clause (iv) of clause (a) of sub-rule (1) of rule 4, shall exercise the powers of a Magistrate of the first class.

79. Judicial trials - All trials in relation to any of the offences specified in sub-section (1) of section 18 of the Act shall be held in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

80. Magistrate - For the purpose of this Chapter 'Magistrate' means the Commandant on whom the powers of a Magistrate have been conferred under sub-section 2(A) of section 18 of the Act.

81. Language to be used in the proceedings before Commandant - Either English or Hindi may be used by the Commandant while exercising the powers of a Magistrate for inquiring into or trying any offence under sub-section (1) of section 18 of the Act.

82. Magistrate not to try enrolled members of the Force - where an enrolled member of the Force is brought before the Magistrate and charged with an offence referred to in sub-section (1) of Section 18 of the Act, for which he is liable to be tried, such Magistrate shall not proceed to inquire into or try the offence unless -

- (a) he is of the opinion for reasons to be recorded in writing that he should so proceed without being moved thereto by the Unit Commander; or
- (b) he is moved thereto by the Unit Commander.

83. Magistrate to give notice - Before proceeding under clause (a) of rule 82, the Magistrate shall give written notice to the Unit Commander and until the expiry of a period of 21 days from the date of service of such notice he shall not :

- (a) convict or acquit the accused under Section 252, section 255(1) and (2), section 256 or section 257 of the Code of Criminal procedure, 1973 or hear him in defence under section 254 of the said Code; or
- (b) frame in writing a charge against the accused under section 238 or section 246(1) of the said Code; or
- (c) make an order committing the accused for trial by the Court of Sessions under section 193 of the said Code; or
- (d) transfer the case for enquiry or trial under section 192 of the said Code.

84. Magistrate to be informed of the trial of the accused -

- (1) When an accused person has been delivered by the Magistrate, the Unit Commander shall, as soon as may, inform the Magistrate whether the accused has been tried by him or any other official proceedings have been taken, ordered to be taken against the accused or not.
- (2) When the Magistrate has been informed under sub-rule(1) that the accused has not been tried or other official proceedings have not been taken or ordered to be taken against him, the Magistrate shall report the circumstances to the Central Government for taking appropriate steps to ensure that the accused person is dealt with in accordance with law.

85. Unit Commander to deliver the accused to the Magistrate—Where an enrolled member of the Force has committed an offence which in the opinion of the Unit Commander is to be tried by a Magistrate in accordance with the law in Force the Unit Commander shall after giving written notice to the Magistrate concerned, deliver such person under proper escort to the Magistrate.

86. Manner of imprisonment—Any enrolled member of the Force sentenced to imprisonment under the Act shall be confined in the nearest jail :

Provided that if the sentence of imprisonment is for one month or less or where the Unit Commander is satisfied that due to the difficulty of transport and escort of the enrolled member of the force sentenced to imprisonment to the nearest jail it is so desirable such person shall be confined in the Quarter Guard of the Force.

87. Force Custody—(1) Where a Unit Commander is of the opinion that any enrolled member of the Force has committed an offence and should be tried by a Commandant who is vested with powers of Magistrate under section 18(2A) it shall be lawful for such Commandant, with the prior approval of the Deputy Inspector General to order the enrolled member of the Force to be taken into Force custody and kept either in close arrest or open arrest as he may deem fit from time to time depending on the gravity of the charge and the attending circumstances;

Provided that no enrolled member of the Force shall be detained in Force custody for a period of more than eight days without a trial having been convened by a Commandant/Magistrate or without a punishment having been awarded to him under section 8 of the Act;

(2) In each unit or group, there shall be one or more places of confinement, as may be considered necessary by the Deputy Inspector General where arrested enrolled member of the Force shall be confined. Such places shall be under the supervision of the Commandant, Deputy Commandant or Assistant Commandant of the Unit, who shall be responsible for their upkeep.

(3) If any enrolled member of the Force in Force Custody escapes or is rescued, the member of the Force from whose custody he escaped or was rescued shall report the escape or rescue to the officer-in-charge of Police Station and may immediately pursue and arrest such enrolled member in any place in India.

88. Promulgation of sentence - The sentence awarded by a Magistrate shall be promulgated at the earliest opportunity after it has been pronounced and shall subject to the provisions of the Act be carried out without delay after promulgation.

89. Transmission of proceedings -(1) The proceeding of every Magistrate without delay be forwarded to the Deputy Inspector General within whose command the trial was held for his information.

90. Appeals - Any person convicted on a trial held by a Magistrate under this Chapter may appeal to the Court of session. The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 relating to appeals in that code shall apply to appeals under this rule.

CHAPTER- XIV

91. Technical consultancy services to the industrial establishments in the private sector - (a) The Central Industrial Security Force may provide technical consultancy services to industrial establishments in the Central/State Government Departments, Public/Joint/Private sector, autonomous bodies or any other institution approved by the Government which may cover :

- (i) Study of industrial security and fire protection related problems and suggesting appropriate solutions.
- (ii) Imparting of knowledge and skills in the field of industrial security and fire protection to the consuler (hereinafter called client) or his employees through training programmes which may be conducted at Central Industrial Security Force Training Institutions or at the client's industrial establishments(s) or at any other place as deemed appropriate by the Director General.
- (iii) To conduct training and certification courses in the fields of Industrial Safety, Security and Fire protection and charge prescribed fees for the same. The fees for various such courses will be determined by the Director General.
- (iv) Planning, designing and effecting industrial security and fire protection schemes measures, controls and systems for the client.
- (v) Providing feed back after monitoring the functioning of suggested measures, controls and systems.
- (vi) Planning and designing of communication network and preparation of related operating instructions.
- (vii) Drafting industrial security and fire protection related instructions, standing orders and standing operating procedures.
- (viii) Preparing disaster management and contingency plan and supervising or conducting rehearsals of such plans.
- (ix) Conducting audits in the field of industrial security, industrial safety or fire safety.
- (x) Undertaking research and development activities independently or in collaboration with the clients and or other reputed agencies in the field of industrial security, industrial safety and fire protection and related matters.
- (b) On receipt of request from the Managing Director of any Industrial Establishment in the Private Sector or any other person authorized by him; in this behalf, subject to any general directions issued by the Central Government, the Director General if deems it appropriate, after examination of the request, may forward terms and conditions of providing Technical Consultancy services to the Managing Director or any other person authorized by him and may ask to remit prescribed fee for technical consultancy services.
- (c) On remittance of prescribed fees from the Managing Director of an industrial establishment in the Private Sector the Director General may nominate any officers of the force or constitute a team of Officers for conducting technical study of the concerned industrial establishment relating to any matter enumerated in sub rule (i) to (x) of rule- 91(a).
- (d) The Director General may, if deems it appropriate and if the nature of consultancy sought so requires, also associate any person(s) expert in the field, expertise whereof is not available with the officers of the force, with the team constituted under sub rule (c).

- (e) The expert person associated with the team under provisions of sub rule (d) shall be paid such amount as deemed appropriate considering his/her expertise, contribution in terms of period of time, services and state of availability of such experts in the given circumstances.
- (f) The officer so nominated or the team so constituted by the Director General under sub rule (c) shall prepare a report after conducting such study as they may deem appropriate and submit the same to the Director General. After due approval of Director General of the Force, the consultancy report, so prepared will be communicated to the Managing Director of concerned industrial establishment in the Private Sector or to the person authorized by him in this behalf.
- (g) The consultancy report so prepared for client(s) establishment shall be the property of that establishment and such reports shall not be used by any member of the Force or by such person associated with the consultancy board for any personal benefit. Such reports, however, can be used for academic purposes.
- (h) CONSULTANCY FEE - The consultancy fees shall be charged from the Industrial Establishments in the Private Sector as prescribed from time to time.

92. Repeal and Saving - (1) The Central Industrial Security Force Rules, 1969 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said rules, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX " A "

See Rule - 21

FORM OF AGREEMENT

To,

The President of India

In consideration of the President of India having agreed to appoint me as

<ul style="list-style-type: none"> *an Inspector *a Sub-Inspector *an Asstt. sub-Inspector *a Head Constable *a Constable 	}	in the Central Industrial Security Force.
--	---	---

I Son of
..... hereby agree and undertake to

- (i) serve in the Central Industrial Security force for a period of not less than ten years with effect from the date of my appointment in the force;
- (ii) Carry out all duties entrusted to me and all lawful orders given to me by my superiors in rank;
- (iii) refund all the cost of training imparted to me in the Force or a sum equal to three months' pay and allowances whichever is more in the event of tendering my resignation from the Force for reasons other than accepting a job elsewhere for which cadre clearance has been given, during the period of my initial training or thereafter during the period of ten years from the date of Joining Central Industrial Security Force; and
- (iv) if, after ten years I desire to resign, I will submit my request in writing and will not Withdraw from my duties until I am duly relieved.

NOTE : The terms pay and allowance used in clause (iii) above means the usual pay and allowances received by him during the period of three months immediately prior to the date of his resignation.

Strike out whichever is not applicable.

Witness

Signature

Designation:

Date

Place

Signature of the employees

Designation:

Date

Place

ACCEPTED

for and on behalf of the
President of India.**APPENDIX "B"**

(Sec Rule - 30)

" I do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to India and to the Constitution of India as by law established and that I will carry out the duties of my office loyally, honestly and with impartiality."

Signature

Signature and designation of the
Supervisory Officer (in whose presence
the affirmation is made)

APPENDIX "C"

See Rule - 17

(MEDICAL EXAMINATION REPORT)
(FOR GROUP C AND GROUP D CISF PERSONNEL)

PART—1

Photo of candidate
attested by the
Chairman of the
Recruitment board

Form to be used when a candidate is granted authority to present himself for medical examination for fitness on appointment.

Name..... Caste or Race

Residence

Father's name and residence

Date of Birth by Christian era as nearly as can be ascertained

Exact height by measurement :

Height.....

Chest.....

Weight.....

Signature of the individual

Station.....

Signature of Appointing Officer

Date.....

Designation.....

PART—2**CANDIDATES STATEMENT AND DECLARATION**

The candidate must make the statement required below, prior to his medical examination and must sign the declaration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in the note below :-

1. (a) Have you ever had a small pox, intermittent or any other fever, Enlargement or suppuration of glands, spitting of blood as heart disease, fainting, attack rheumatish ?
- (b) Any other disease or accident requiring confinement to bed and prolonged medical or surgical treatment.
2. When you were last vaccinated ?

3. Have you or any other relative been affected with consumption, sorofulous, gout asthma, fits, epilepsy or insanity ?
4. Have you suffered from any form of nervousness due to overwork or any other cause ?
5. Have you been examined and declared unfit for Government service by medical officer/medical Board within the last three years.

I declare that all the above answers are to the best of my belief true and correct. I also solemnly affirm that I have not received disability/certificate/pension on account of any disease or other condition.

Candidate's Signature

Signed in my presence

NOTE :— The candidate will be held responsible for accuracy of the above statement, by willfully suppressing any Information will incur the risk or losing the appointment and if appointed of forfeiting all the superannuation allowances or gratuity.

PART—3

It is certified that I/We have examined
S/o a candidate for employment in the Central Industrial Security Force and can not discover that he has any disease, constitutional affliction or bodily infirmity excluding knock knee, flat feet and

I/We considered/do not considered this a disqualification for employment in Central Industrial Security Force. His age according to his own statement is

This may be filled up after examining the candidate for knock knee, flat feet, bow legs, squint eyes, inability close the left eye, inability to flax the fingers properly, varicose veins or any other obvious disabilities which are likely to affect his functioning as a member of the Central Industrial Security Force.

- | | | | |
|--|-------|---------|-------|
| 1. General Development | Good | Fair | Poor |
| 2. Body built | Thin | Average | Obese |
| 3. Eyes | Right | Left | |
| (A) Any obvious Disease | | | |
| (i) External | | | |
| (ii) Media | | | |
| (B) Visual Acuity | | | |
| (i) Distant | | | |
| (ii) Near | | | |
| (C) Colour Vision | | | |
| 4. Ear, Nose & Throat | Right | Left | |
| (a) Any obvious disease | | | |
| (b) Hearing | | | |
| (c) PNS | | | |
| 5. Condition of teethDental points | | | |
| 6. Respiratory System | | | |
| (i) Appearance of Chest | | | |
| (ii) Breathing Rate | | | |

- (iii) Any abnormality on stethoscopic examination.
7. (A) Circulatory System
Heart : Any organic lesion
Rate : Standing
After hopping 25 times
2 Minutes after hopping.....
- (B) Blood pressure
Systolic
Disstolic.....
8. Abdomen
(a) Tenderness
(b) Palpability
(i) Liver :
(ii) Spleen :
(iii) Kidneys :
(c) Haemorrhoids :
(d) Fissure/fistula :
(e) Hernia/Hydrocele :
(f) Any other :
9. Locomotor System :
(i) Condition of spine
(ii) Condition of limb joints :
10. Nervous System :
(i) Evidence of nervous instability :
(ii) Tremers :
(iii) History of Mental Disease :
11. Report of Radiological examination of chest if done :
12. Is there anything in the health of candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties on the service for which he is a candidate ?
13. State the service for which the candidate has been examined (GD/Follower/Trades/Communication/Medical etc).
14. Small pox vaccination marks (Give number & site)
15. Mild defects noted, not sufficient for rejection
16. Out line reasons declaring candidate unfit.
17. UNFIT/TEMPORARY UNFIT/FIT

Signature of the candidate

Place :

Date :

Signature of Medical Officer with date

1.

2.

Appendix - 'D'**DISCHARGE CERTIFICATE**

(Under Rule 59 of CISF Rules, 2000)

PARTICULAR

1. Name
2. Father's Name
3. Religion
4. Whether Scheduled Caste/Scheduled Tribe
5. Date of Birth
6. Identification mark, if any
7. Branch of the CISF in which deployed (Executive/Fire/Ministerial)
8. Period of Service from to.....
9. Date of issue of appointment certificate [See Section 6 (1) of CISF Act, 1968 as modified by Act, 1983 and 1989].
10. Date of surrender of certificate referred to in item 9 above [See Section 6(2) of the CISF Act, 1968 as amended by Act, 1983 and 1989].
11. Post held immediately prior to ceasing to be the member in the service
12. Pay prior to ceasing to be member in the service
13. Reasons for discharge
14. Medals/Decorations awarded
15. Character
16. Employee's signature or thumb impression.

Place : _____ Signature and designation
Date : _____ of Supervisory Officer.

Following criteria will be adopted for assessment of "Character" in the discharge certificate :—

S.No.	Category of assessment	Conditions
1.	Exemplary	(i) Minimum 10 years service with the Central Industrial Security Force. (ii) No punishment under the Central Industrial Security Force Act or in Civil/Criminal Court. (iii) Quality of ACR.
2.	Very good	(i) Minimum 7 years service with the Central Industrial Security Force. (ii) No punishment under section 8 (i) and 18 of Central Industrial Security Force Act or in the Civil/Criminal Court. (iii) Quality of ACR.
3.	Good	(i) At least 3 year's service with the Central Industrial Security Force without any major or minor punishment under Central Industrial Security Force Act and Rules. (ii) No reduction in rank or grade for an offence under the Central Industrial Security Force Act and Rules. (iii) Quality of ACR.
4.	Fair	(i) Not more than one reduction in rank or grade for offence under the Central Industrial Security Force Act and Rules.
5.	Bad	(i) Cases not covered under item (1) to (4) above. (ii) More than two reduction in rank or grade for offence under Central Industrial Security Force Act and Rules.

SCHEDULE -I

See Rule -32

**SCHEDULE OF DISCIPLINARY AUTHORITIES AND THEIR POWERS TO PASS DIFFERENT
DISCIPLINARY ORDERS IN RESPECT OF DIFFERENT CLASSES AND GRADES AND
RANKS OF MEMBERS OF THE FORCE**

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Removal from an office of distinction or deprivation of special emoluments.	All enrolled member of the force	All enrolled member of the force	All enrolled member of the force	All enrolled member of the force	All enrolled member of the force	All enrolled member of the force
10.	Fine to an amount not exceeding seven days pay	All enrolled member of the force	All enrolled member of the force	All enrolled member of the force	All enrolled member of the force	All enrolled member of the force	All enrolled member of the force
11.	Censure	All enrolled member of the force	All enrolled member of the force	All enrolled member of the force	All enrolled member of the force	All enrolled member of the force	All enrolled member of the force
12.	Punishment, drill, extra guard, fatigue, or other duty	Head Constable/ Constable/ Followers	Head Constable/ Constable/ Followers	Head Constable/ Constable/ Followers	Head Constable/ Constable/ Followers	Head Constable/ Constable/ Followers	Head Constable/ Constable/ Followers

[No. E-32012/2/84-L&R/Pers-1]

O.P. ARYA, Jt. Secy. (Police)